

भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश

विषय सूची

एक लक्ष्य सबसे आगे मध्य प्रदेश

	मुख्यमंत्री का संदेश	04
	प्रदेश अध्यक्ष का संदेश	05
	संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष का संदेश	06
	20 साल विश्वास के, 20 साल विकास के	08
	मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा मुख्य संकल्प	09-14
	सशक्त नारी	15-20
	समृद्ध किसान	21-32
	जनजातीय कल्याण	33-38
	उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा	39-46
	सबका साथ सबका विकास	47-56
	सुदृढ़ आधारभूत संरचना	57-64
	स्वस्थ प्रदेश	65-70
	प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास	71-78
	सुशासन एवं कानून व्यवस्था	79-84
	सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन	85-92

मुख्यमंत्री का संदेश

मेरे प्यारे प्रदेश वासियो,

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आप सभी के विश्वास, सहयोग एवं आशीर्वाद से हमारा मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास कर रहा है।

2003 के पहले खस्ताहाल सड़कें, बिजली की आंख मिचौली, सिंचाई के अभाव में सूखे की मार झेलते किसान और बीमारू-पन मध्य प्रदेश की पहचान थी। भाजपा सरकार ने 2003 से मध्य प्रदेश के कायाकल्प का अभियान प्रारंभ किया, जिसमें हमने मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और पानी पर खास तौर पर

ध्यान दिया जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। तब प्रदेश में सड़कें मात्र 60 हजार किलोमीटर लंबी थी, जो अब बढ़कर 5 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। तब सिर्फ कुछ घंटे ही बिजली मिलती थी और अब 24 घंटे बिजली मिल रही है।

भाजपा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमने महिलाओं के लिए लाइली बहना, किसानों के लिए कृषक ब्याज माफी एवं श्रमिकों के लिए संबल योजना जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से हमारी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के सभी इलाकों के विकास एवं हर नागरिक का कल्याण करने की जिम्मेदारी उठाई है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर गरीब कल्याण का लक्ष्य लेकर अनवरत आगे बढ़ रही है।

आज हम फिर आपके सामने प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर आए हैं। यह संकल्प पत्र 2023 प्रदेश की जनता के लिए हमारा विज़न है और इसे पूर्ण करने के लिए हम संकल्पित हैं।

आपका,



शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश



प्रदेश अध्यक्ष का संदेश

मेरे प्यारे प्रदेश वासियो,

आपको याद होगा कि साल 2003 से पहले मध्य प्रदेश का क्या हाल था। चारों तरफ फैली भुखमरी, अव्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार और नक्सलियों के आतंक ने प्रदेश को बुरी तरह जकड़ रखा था। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को एक 'बीमारु' प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

गरीबों और वंचितों के लिए शुरु की गई योजनाओं ने उन्हें नई उम्मीद और अवसर दिए हैं। उत्तम शिक्षा, स्वस्थ समाज, रोजगार एवं विकास के लिए शुरु की गई योजनाएं दर्शाती हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र को आम जनता के जीवन में उतारने के लिए संकल्पित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। हमारा निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन सुगम्य हो और हर घर में समृद्धि आए। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि आप इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका अवश्य देंगे।

भारत माता की जय।

आपका,

वी.डी. शर्मा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश



संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष का संदेश

मेरे प्यारे भाइयो एवं बहनो,

आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी दो दशकों से जनता की सेवा कर रही है। दो दशकों के इस कालखंड में हमने प्रदेश को बीमारू हालत से बाहर निकालकर देश की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में शामिल किया है।

हमने यह संकल्प पत्र तैयार करने के पहले लोगों के सुझाव एकत्रित करने की पहल की। हमने हर गांव, कस्बे, तहसील और जिले से प्राप्त हुए लाखों सुझावों से यह संकल्प पत्र बनाया है और

इस संकल्प पत्र में प्रदेश के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को समाहित करने का प्रयास किया है। हमने प्रदेश के बुद्धिजीवियों, विविध समुदायों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ सहयोग करके यह सुनिश्चित किया है कि हमारे सभी संकल्प मध्य प्रदेश की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें।

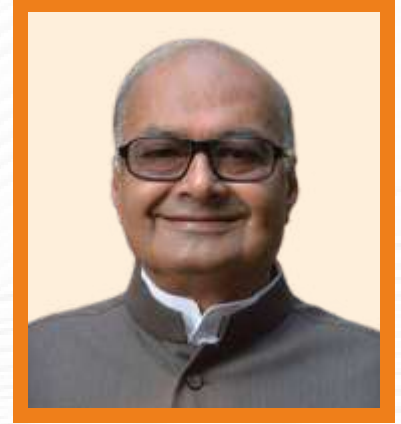
जनता के सुझावों पर गंभीर विचार करके हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र को व्यक्त करने का प्रयास किया है। नागरिकों की सेवा भाजपा का एकमात्र धर्म है। इस आस्था के साथ यह संकल्प पत्र हमारे लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह प्रदेश के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता प्रकट करने का एक माध्यम भी है। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आप हमारा समर्थन अवश्य करेंगे।

आपका,

जयंत मलैया

जयंत मलैया

अध्यक्ष, घोषणा पत्र समिति
भाजपा, मध्य प्रदेश





मध्य प्रदेश संकल्प पत्र समिति सदस्य

प्रमुख

श्री जयंत मलैया

सह प्रमुख

श्री प्रभात झा

सदस्य

श्री राजेन्द्र शुक्ला
श्री अजय विश्वोई
श्री ओमप्रकाश सकलेचा
श्री लाल सिंह आर्य
श्रीमती लता वानखेड़े
श्री ओमप्रकाश धुर्वे
श्री सुमेर सिंह सोलंकी
श्री डी.डी. उइके

श्री राज्यवर्धन सिंह
श्री अजय प्रताप सिंह
श्री कवीन्द्र कियावत
श्री दीपक विजयवर्गीय
श्री एस.एन.एस. चौहान
श्री अतुल सेठ
श्री मनोज पाल यादव
श्री पुष्यमित्र भार्गव
डॉ. विनोद मिश्रा

भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश

20 साल विश्वास के विकास के

2003 के पहले

भाजपा सरकार (2023)

प्रति व्यक्ति आय
तब ₹11,718 प्रति वर्ष



प्रति व्यक्ति आय में 12 गुना की वृद्धि
अब ₹1.40 लाख प्रति वर्ष है

प्रदेश की कुल आय
तब ₹71,594 करोड़



प्रदेश की कुल आय में 18 गुना की वृद्धि
अब ₹13,22,821 करोड़ है

बिजली उपलब्धता तब 2-3 घंटे



बिजली उपलब्धता अब 24 घंटे है

फसल ऋण ब्याज दर
तब 15-16%



फसल ऋण ब्याज दर अब 0%, ₹1.5
लाख करोड़ का ऋण वितरित किया है

सिंचाई क्षमता
तब 7.68 लाख हेक्टेयर



सिंचाई क्षमता में 6 गुना की वृद्धि
अब 47 लाख हेक्टेयर है

शासकीय विद्यालयों की संख्या
तब 71,691



शासकीय विद्यालयों की संख्या
अब 1,81,063 है

तब जनजातीय समुदाय के लोग
अपने अधिकारों से वंचित थे



पेसा नियमों के क्रियान्वयन से
1 करोड़ से अधिक लोग हुए लाभान्वित

मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल सीटें
तब 5 एवं 620



मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल सीटें
अब 25 एवं 4,000 से अधिक है

सड़कों की लम्बाई
तब 60,000 किमी



सड़कों की लम्बाई में 9 गुना वृद्धि
अब 5.10 लाख किमी है



सशक्त नारी

- लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा आवास
1.3 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेगा लाभ
- ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे
15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का लाभ
- लाड़ली लक्ष्मियों को कुल ₹2 लाख
सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक लाभ
- ₹450 में सिलेंडर
पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों को मिलेगा
- केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
सभी बीपीएल परिवार की छात्राओं को मिलेगा लाभ



समृद्ध किसान

- एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था
₹2,700 प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद
₹3,100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीद
- ₹12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता
पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को लाभ देते रहेंगे





जनजातीय कल्याण

- जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए ₹3 लाख करोड़
अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर व्यय
- तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹4,000 प्रति बोरा
सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ
- प्रत्येक एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना
साथ ही 3,800 शिक्षकों की भर्ती
- एसटी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण
मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट एवं सीधी में मेडिकल कॉलेज
- पूजा स्थलों का विस्तार एवं नवीनीकरण
₹100 करोड़ के निवेश के साथ जनजातीय श्रद्धा-स्थल संरक्षण मिशन



उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा

- गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा
₹1,200 की वार्षिक सहायता स्कूल बैग, किताबों एवं यूनिफॉर्म के लिए
- मिड-डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को लाभ
- प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी
आई.आई.टी के तर्ज पर बनेगा
- प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर
केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन
- युवाओं को ₹10,000 तक का स्टाइपेंड
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

○ प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना करेंगे

वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स
योजना के अंतर्गत



सबका साथ सबका विकास

○ 5 वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार

सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन एवं
रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं
चीनी

○ प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे

○ ₹1,500 की मासिक पेंशन वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभ

○ गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना

गिग वर्कर्स के कल्याण एवं
अधिकारों की देखरेख

○ कारीगरों को ₹15,000 की वित्तीय सहायता, ₹500 का दैनिक भुगतान

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत
18 पारंपरिक कारीगर समूहों को लाभ

○ असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

ई-श्रम पोर्टल, आयुष्मान भारत के
अंतर्गत 100% पंजीकरण





सुदृढ़ आधारभूत संरचना

- क्षेत्रीय विकास के लिए 3 विकास बोर्ड**
 बुंदेलखंड, विंध्य एवं महाकौशल विकास बोर्ड
- ₹100 में 100 यूनिट बिजली**
 अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत सभी घरों को लाभ
- 6 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण शीघ्र**
 विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा-निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ एवं मध्य भारत विकास पथ
- केंद्र सरकार के साथ मिलकर**
 - 80 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय आधुनिकीकरण
 - वंदे मेट्रो एवं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
 - रीवा,सिंगरौली एवं शहडोल में हवाई अड्डे
- भोपाल, इंदौर,ग्वालियर, जबलपुर में मेट्रो**
 भोपाल एवं इंदौर मेट्रो लाइनों का पूर्ण निर्माण और ग्वालियर एवं जबलपुर में मेट्रो लाइनों के लिए प्लान



स्वस्थ प्रदेश

- ₹5 लाख से ज्यादा व्यय होने पर भी प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी**
 आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को सीएम रिलीफ फण्ड के अंतर्गत लाभ
- ₹20,000 करोड़ के निवेश से सुचारु स्वास्थ्य व्यवस्था**
 - प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
 - अटल मेडिसिटी
 - हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या दोगुना
- मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि**
 प्रत्येक लोकसभा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करके अगले 5 वर्षों में और 2,000 सीटें जोड़ेंगे
- डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां शीघ्र भरेंगे**
 प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे



प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास

○ प्रदेश को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाएंगे

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 7 वर्ष में ₹45 लाख करोड़ की बनाएंगे

○ प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे

साथ ही ₹20 लाख करोड़ के निवेश (FDI) आकर्षित करेंगे

○ एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण

4.5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

○ 10 नए एमएसएमई क्लस्टर

₹5,000 करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों को न्यूनतम दर पर ऋण



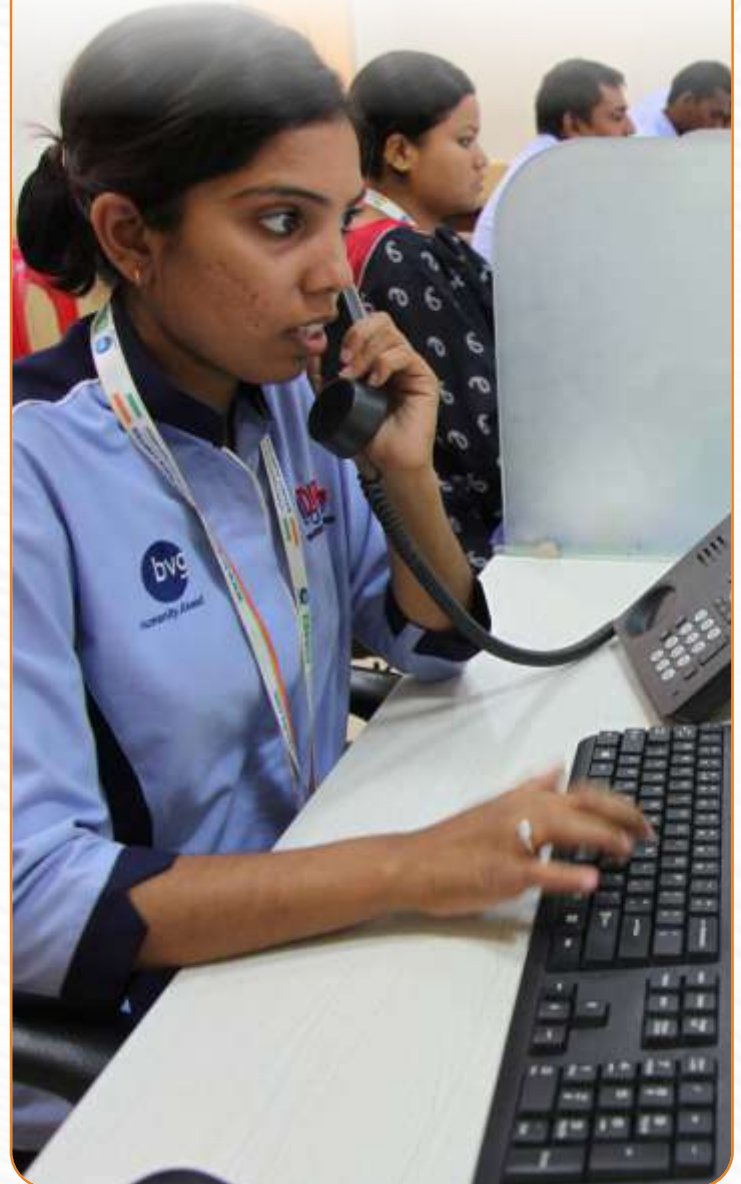
सुशासन एवं कानून व्यवस्था

○ कमिश्नर प्रणाली का विस्तार

भोपाल एवं इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में लागू करेंगे

○ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण

भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय





सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन

○ शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक निर्माण

साथ ही ₹150 करोड़ के निवेश से धरोहर संरक्षण मिशन शुरू करके सभी ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण

○ भाषाई साहित्य अकादमियों की स्थापना

बघेली, बुंदेली, गोंडी एवं भीली साहित्य अकादमी

○ सभी जनजातीय नायकों के भव्य स्मारकों का निर्माण

साथ ही चौगान किला, देवगढ़ किला, मंडला किला, चौरागढ़ किला एवं मदन महल किला का नवीनीकरण

○ 13 सांस्कृतिक लोकों का निर्माण

प्रदेशवासियों की श्रद्धा का सम्मान

○ शक्तिपीठों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव

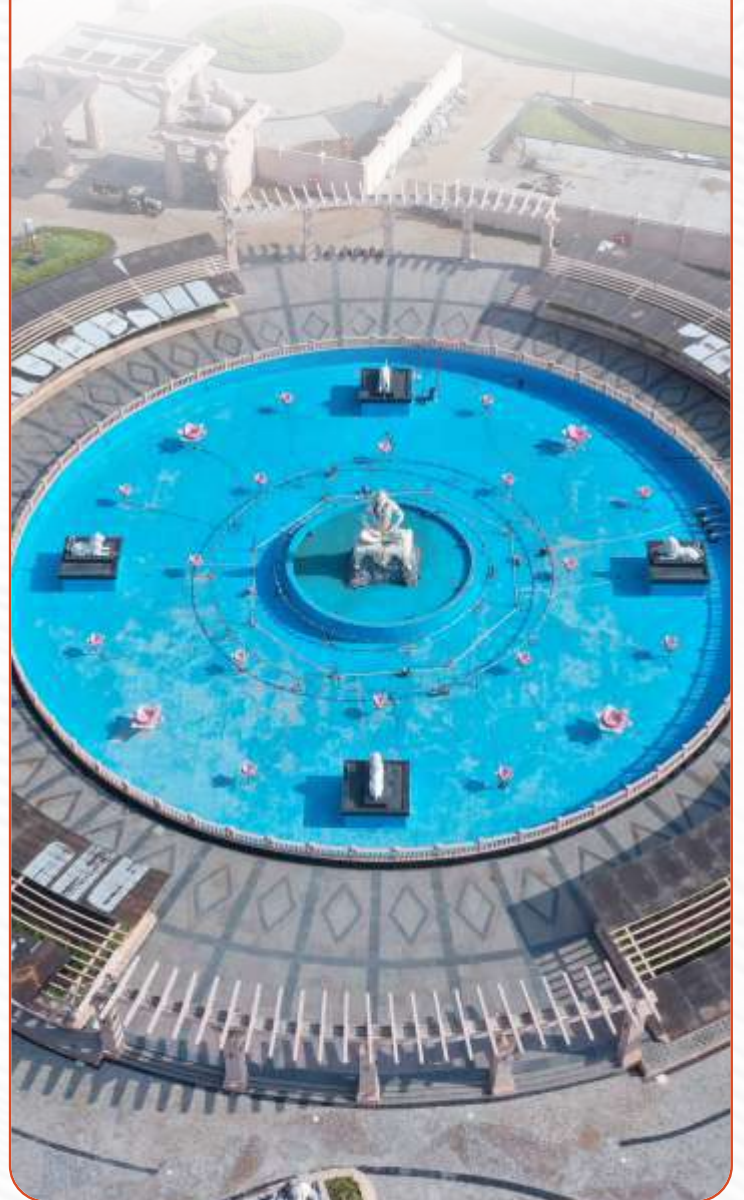
मैहर में शारदा माता मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा देवी शोणदेश शक्तिपीठ, उज्जैन में हरसिद्धि माता शक्तिपीठ

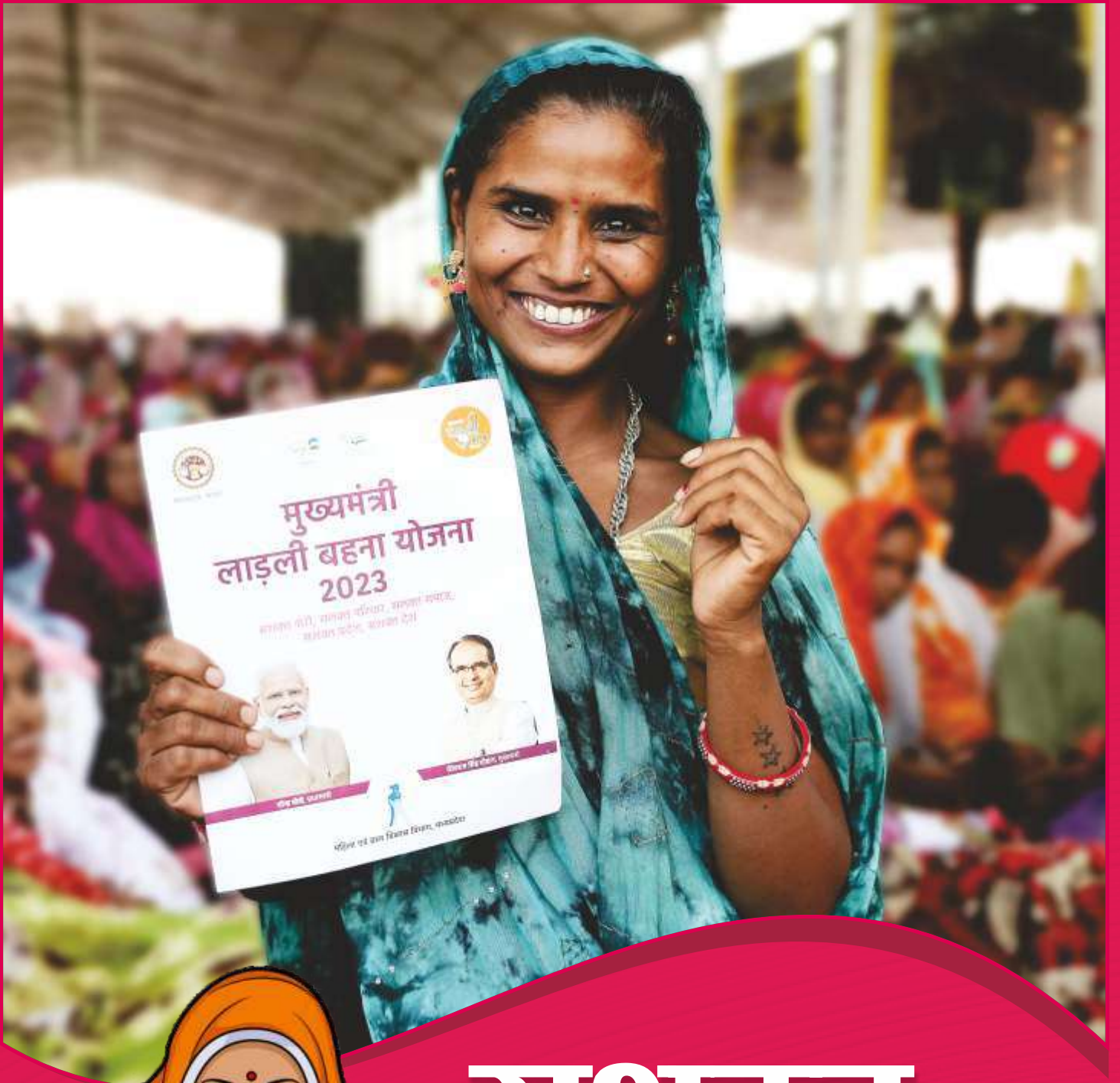
○ नमामि नर्मदे परियोजनाओं को पूर्ण

नर्मदा, ताप्ती एवं क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों के घाटों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण

○ पर्यटन कौशल कोष

₹7,500 करोड़ के निवेश के साथ 2 लाख युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर





सशक्त नारी

20 साल विश्वास के विकास के

नारी कल्याण के क्षेत्र में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 46 लाख बेटियां लखपति बनीं हैं एवं 13 लाख से अधिक बेटियों को स्कॉलरशिप मिली है

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1.31 करोड़ से अधिक महिलाओं को ₹1,250 प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं

4.99 लाख से अधिक नए एसएचजी बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 61 लाख महिलाएं जुड़ी हैं एवं इन्हें ₹6,000 करोड़ से अधिक का क्रेडिट लिन्केज प्रदान किया गया है

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 82.2 लाख से अधिक महिलाओं को रसोई के काले धुएं से छुटकारा मिला है

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों में महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में 52% एवं शहरी क्षेत्रों में 70% से अधिक का मालिकाना हक दिया गया है

महिलाओं की अस्मिता से छेड़छाड़ करने वालों को फांसी की सजा देने का कानून लाने वाला देश का पहला प्रदेश है

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 44 लाख से अधिक माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

बालिकाओं का उज्ज्वल भविष्य

- मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुल वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹1.43 लाख से ₹2 लाख करेंगे, जिससे प्रत्येक लाड़ली को मिलेगा:
 - ◆ कक्षा 6 में ₹2,000 से बढ़कर ₹5,000
 - ◆ कक्षा 9 में ₹4,000 से बढ़कर ₹8,000
 - ◆ कक्षा 11 में ₹6,000 से बढ़कर ₹10,000
 - ◆ कक्षा 12 में ₹6,000 से बढ़कर ₹12,000
 - ◆ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में ₹25,000 से बढ़कर ₹40,000
 - ◆ 21 वर्ष की उम्र में वर्तमान ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.25 लाख
- हम प्रदेश की सभी बीपीएल परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम बालिकाओं को सशस्त्र एवं पुलिस बल में शामिल करने के लिए, प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे।
- हम ₹50 करोड़ के निवेश के साथ लाड़ली छात्रावास उन्नयन योजना की

शुरुआत करके, सभी बालिका आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ अपग्रेड करेंगे।

- हम उच्च शिक्षा में बालिकाओं के एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मी बाई विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी मेधावी छात्राओं को आगे भी स्कूटी प्रदान करेंगे।

आर्थिक सशक्तिकरण

- हम 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करते रहेंगे।
- हम सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, पुलिस में 35% आरक्षण एवं शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण का सफल क्रियान्वन करके, प्रदेश में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे।
- हमने 4.99 लाख एसएचजी के साथ 61 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा है, और अब लाड़ली शक्ति एसएचजी मिशन शुरू करके एसएचजी की संख्या को दोगुना करेंगे एवं उन्हें सरल ऋण

सुविधाएं एवं मार्किट लिन्केज की सुविधा प्रदान करेंगे।

- हम एसएचजी में काम करने वाली लगभग 61 लाख महिलाओं को लाइली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से न्यूनतम दर पर ₹1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- हम लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम ₹1 लाख हो, यह सुनिश्चित करेंगे।
- हम प्रदेश में महिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (आईटीआई) की संख्या में वृद्धि करके 2 लाख महिलाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में दीदी कैफ़े का संचालन प्रारंभ करेंगे।
- हम लाइली प्रतिभा खोज योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत चुनी गई सभी महिला एथलीट को ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम शुरू करके महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे।

सामाजिक सशक्तिकरण

- हम लाइली बहना आवास योजना शुरू करके, उन सभी बीपीएल परिवार की महिलाओं को पक्के घर प्रदान करेंगे जो पीएम आवास योजना में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं।
- हम पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाइली बहना योजना की सभी लाभार्थियों को ₹450 में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को ₹55,000 तक बढ़ा चुके हैं, आगे इसे ₹1 लाख तक बढ़ाएंगे।
- हम विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,500 करेंगे।
- इंदौर की पिंक बसों की तर्ज पर, हम सभी प्रमुख शहरों में महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए पिंक बस का नेटवर्क शुरू करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ मिशन पिंक-टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के लिए मौजूदा शौचालयों का नवीनीकरण, नए शौचालयों का निर्माण और उनके रख-रखाव के लिए स्वच्छता सखियों को नियुक्त करेंगे।

सुरक्षित वातावरण

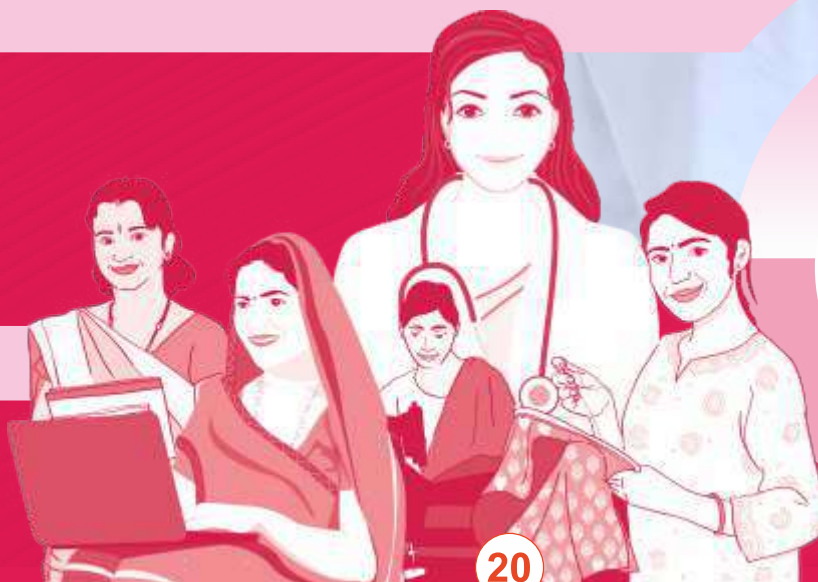
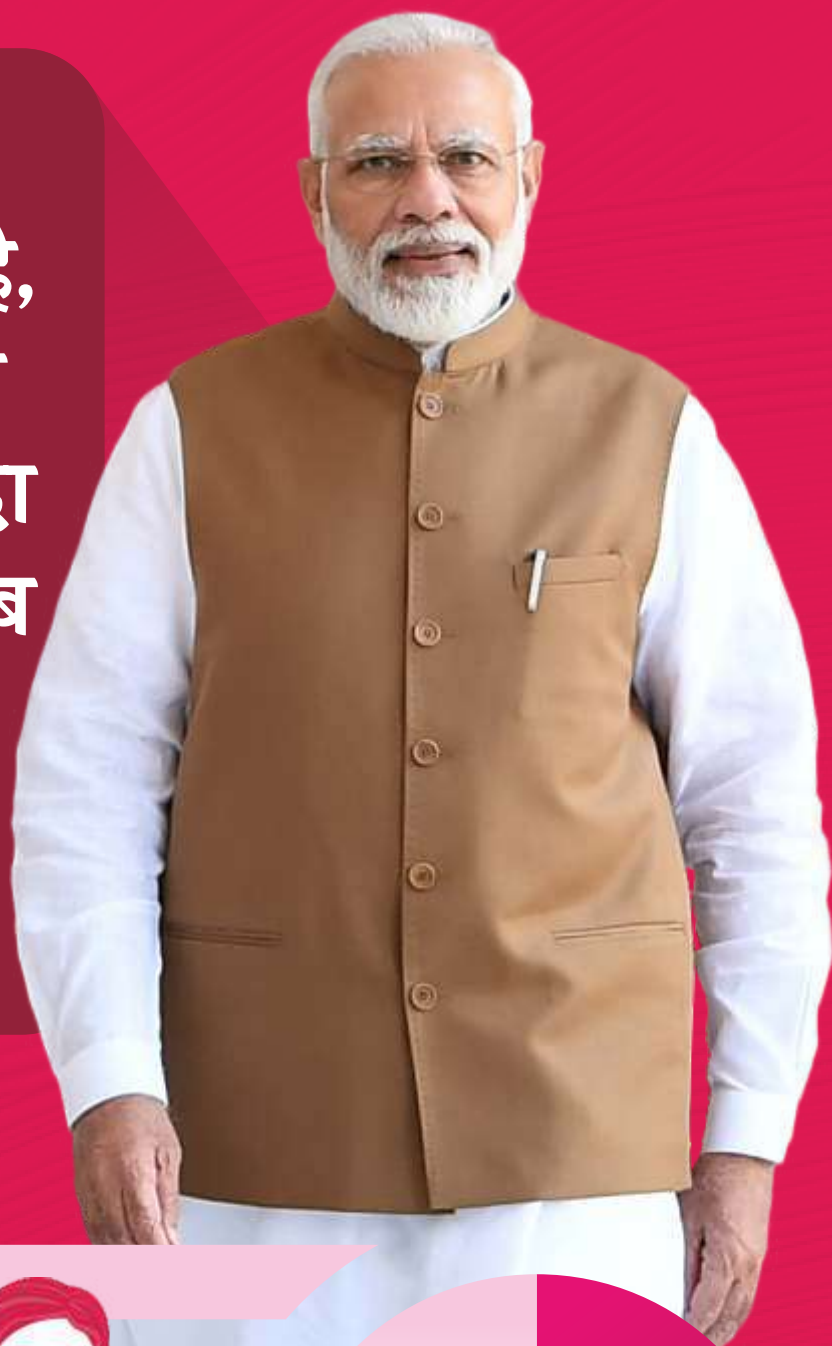
- हमने 10 महिला पुलिस थाने स्थापित किए हैं, और अगले 5 वर्षों में हम हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम सभी पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क स्थापित करेंगे।
- हम मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन- नर्मदा, क्षिप्रा एवं ताप्ती स्थापित करेंगे।
- हम सभी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे एवं पेट्रोलिंग वैन के साथ पिंक बूथ स्थापित करेंगे।

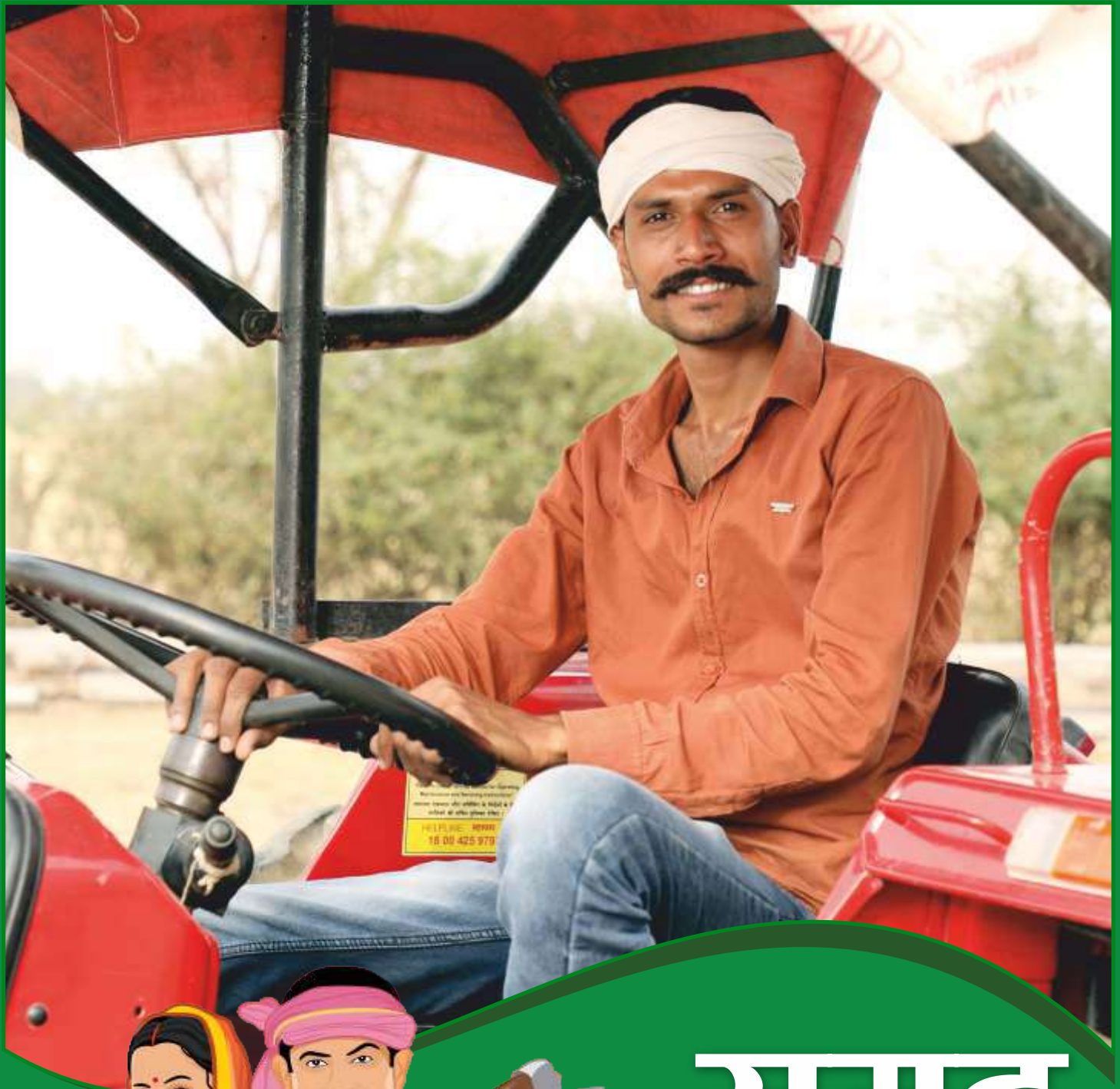
विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ

- हम पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 करेंगे एवं इसका 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे।
- हम 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हासिल करने के लिए, प्रदेश के हर संभाग में एक मातृ वंदना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करेंगे।

- हम प्रत्येक जिला अस्पताल में नियोनेटल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू एवं ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू की स्थापना करेंगे।
- हम सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र एवं सार्वजनिक संस्थान में सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी शिशुओं एवं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आयरन टेबलेट जैसी उपयोगी वस्तुओं से युक्त पोषण किट वितरित करेंगे।
- हम बेहतर पोषण सुनिश्चित करने एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या में वृद्धि करेंगे।
- हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सभी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन के साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की मुफ्त जांच की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेंगे।

“
महिला - वो शक्ति है,
सशक्त है, वो भारत
की नारी है, न ज्यादा
में, न कम में, वो सब
में बराबर की
अधिकारी है
”





समृद्ध किसान

किसानों को समृद्ध बनाने में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 80 लाख से अधिक किसानों को वार्षिक ₹12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है

पिछले 3.5 वर्षों में किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹3 लाख करोड़ से अधिक के कुल लाभ दिए गए हैं

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना से प्रदेश के 11.9 लाख किसानों के ऋण का ₹2,123 करोड़ ब्याज माफ किया गया है

पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को पिछले 3 वर्षों में ₹20,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है

₹44,600 करोड़ से अधिक लागत की केन-बेतवा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिल गई है

5 हॉर्स पावर तक के पंप उपयोग करने वाले 32 लाख किसानों को बिजली बिल पर 93% सब्सिडी दी जा रही है

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है

प्रदेश के पशुपालकों को पशु उपचार की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराते हुए 400 से अधिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का संचालन प्रारंभ किया गया है

80 हजार से अधिक मछुवा क्रेडिट कार्ड जारी कर मध्य प्रदेश, देश में अग्रणी है

किसान कल्याण को प्राथमिकता

- हम सभी किसानों को ₹12,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता, पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान करते रहेंगे।
- हम सभी इच्छुक किसानों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन, पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के नुकसान का समय पर आकलन एवं राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करेंगे।
- हम ₹1,500 करोड़ के निवेश के साथ अन्नदाता शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर श्रमिकों एवं बटाईदार किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम 1,000 नए फसल-विशिष्ट एफपीओ सस्थापित करके प्रत्येक एफपीओ को ₹18 लाख तक की वित्तीय सहायता एवं ₹5 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान करेंगे।

कृषि उत्पादकता को बढ़ावा

- हमने 2012 से 0% ब्याज दर पर लगभग ₹1.4 लाख करोड़ का फसली ऋण प्रदान किया है, और आगे भी किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान करते रहेंगे।
- हम बीज, फर्टिलाइज़र, मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करेंगे।
- हम 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करके किसानों को सस्ते दाम में कृषि उपकरण उपलब्ध कराना जारी रखेंगे।

सिंचाई क्षमता का विस्तार

- हम कृषि के लिए 10 घंटे की निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते रहेंगे।
- हमने 2003 में प्रदेश में सिंचाई क्षमता 7.6 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2023 तक 47 लाख हेक्टेयर कर दी है। हम इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- हम 4 लाख हेक्टेयर तक की उपजाऊ भूमि में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करेंगे।
- हम प्रदेश के डार्क जोन क्षेत्रों में बोरवेल, टैंक और सिंचाई के अन्य स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे एवं ₹1,500 करोड़ का निवेश करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करेंगे।
- हम पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों का 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करेंगे।



हर खेत को पानी उपलब्ध कराना हमारा संकल्प



हम मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन करेंगे
जो प्रदेश में ₹32,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को
समय पर पूरा करेगी



ग्वालियर एवं चंबल में माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना



नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद में चिंकी-बोरास बैराज परियोजना



नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा में शक्कर-पेंच लिंक संयुक्त परियोजना



छिंदवाड़ा में पेंच डायवर्सन परियोजना



खंडवा में खंडवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना



पन्ना में रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना



पन्ना, रीवा, सतना, कटनी एवं जबलपुर में बरगी परियोजना



कटनी में बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना



हरदा में शहीद इलाप सिंह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना



श्योपुर में चेंटीखेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना



सतना एवं रीवा में बहुती नहर परियोजना

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अनुसंधान

- हम ₹25,000 करोड़ के निवेश के साथ एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे।
- हम गेहूं एवं धान जैसी फसलों को सीधे किसानों से खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट वैन का नेटवर्क शुरू करेंगे।
- हम कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फण्ड स्थापित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में कृषि निर्यात के मौजूदा मूल्य को दोगुना करेंगे।

कृषि आय में वृद्धि

गेहूं

- हम गेहूं की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करके ₹2,700 प्रति क्विंटल पर खरीद सुनिश्चित करेंगे।

- हमने यह सुनिश्चित किया है कि देश में गेहूं की दूसरी सबसे ज्यादा खरीद मध्य प्रदेश से हो, हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा एमएसपी पर गेहूं की खरीद की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।
- हम गेहूं के मुख्य उत्पादन वाले जिलों में पर्याप्त संख्या में गोदाम स्थापित करेंगे।
- हम गेहूं की देसी फसलों की खेती को बढ़ावा देंगे।

धान

- हम धान की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करके ₹3,100 प्रति क्विंटल पर खरीद सुनिश्चित करेंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा एमएसपी पर धान की खरीद की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।
- हम धान के मुख्य उत्पादन वाले जिलों में पर्याप्त संख्या में गोदाम स्थापित करेंगे।
- हम धान की देसी फसलों की खेती को बढ़ावा देंगे।

सोयाबीन

- हम मध्य प्रदेश में मिशन सोयाबीन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सोयाबीन का उत्पादन और बढ़ाएंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद को और मजबूत करेंगे।

- हम प्रदेश में सोयाबीन-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे एवं एफपीओ को सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

श्री अन्न (मोटा अनाज)

- हम राज्य मिलेट (श्री अन्न) मिशन के अंतर्गत कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा एवं रागी का उत्पादन बढ़ाएंगे।
- हम जनजातीय बहुल क्षेत्रों में श्री अन्न (कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा आदि) की खेती का क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ाएंगे।
- हम प्रदेश में श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेंगे, जिससे श्री अन्न के उत्पादन एवं प्रचार को बढ़ावा देंगे।
- हम श्री अन्न-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री अन्न की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू चेन को बढ़ावा देंगे।
- हम डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेंगे।
- हम श्री अन्न की खेती करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्राप्त राशि के अतिरिक्त ₹1,000 प्रति एकड़ प्रति फसल सम्मान राशि देंगे।

- हम श्री अन्न की फसल बोने पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम में सब्सिडी प्रदान करेंगे।

दाल

- हम मध्य प्रदेश में मिशन दाल शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में दाल उत्पादन बढ़ाएंगे।
- हम सरकार द्वारा एमएसपी पर अरहर, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों की खरीद की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।
- हम दाल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत दाल की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू चेन को बढ़ावा देंगे।
- हम उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान स्थापित करेंगे।

सरसों

- हम सरसों उत्पादन को और बढ़ाएंगे एवं देश के अग्रणी सरसों उत्पादक प्रदेशों में से एक बने रहेंगे।
- हम सरसों के मुख्य उत्पादन वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में सरसों खरीद केंद्र स्थापित करेंगे।
- हम सरसों-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे एवं एफपीओ को सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

- हम ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान स्थापित करेंगे।

बागवानी

- हम बागवानी का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर कर बागवानी के उत्पादन में प्रदेश को अन्य राज्यों के मुकाबले आगे लेकर जाएंगे।
- हम वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत हर जिले में हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करेंगे, जिसमें प्याज, आलू, टमाटर, संतरा, केला आदि की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू चेन को सुनिश्चित करेंगे।
- हम मशीनीकरण एवं सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं के साथ प्रदेश के हर संभाग में हाई-टेक नर्सरी स्थापित करेंगे एवं सभी मौजूदा नर्सरी को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करते रहेंगे।
- हम प्रदेश में हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करके बागवानी फसलों के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देंगे।
- हम मध्य प्रदेश फ्लोरीकल्चर मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश को नंबर 1

बनाएंगे एवं प्रमुख हवाई अड्डों के पास प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करेंगे।

दुग्ध क्रांति

- हम दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी सहकारी समिति एवं कलेक्शन सेंटर स्थापित करेंगे।
- हम श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत ₹2,500 करोड़ के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिलक कूलर, मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि करेंगे, जिसके अतिरिक्त सभी दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में भी विस्तार करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी डेयरी किसानों को 0% ब्याज पर ₹1 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए ग्वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च शुरू करेंगे।
- हम इच्छुक किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए ₹40,000 का अनुदान प्रदान करेंगे एवं इन गायों के पालन-पोषण के लिए हर महीने ₹900 प्रदान करना जारी रखेंगे।

पशुपालन

- हम आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करेंगे।
- हम ₹25 करोड़ के निवेश के साथ पशुपालन कल्याण कोष बनाएंगे, जिसके अंतर्गत लम्पी स्किन डिजीज, एंथ्रेक्स, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के कारण पशुओं की बीमारी के इलाज या पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत सभी दुधारू एवं अन्य पशुओं के लिए मुफ्त बीमा एवं उनके रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे।
- हम सभी किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय स्थापित करेंगे, साथ ही इन चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की पर्याप्त नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
- हम बीमार एवं सड़क हादसों में घायल गोवंशों के उपचार के लिए आवश्यकता अनुसार पशु एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि करेंगे।
- हम 10 गौवंश विहारों की स्थापना

जल्द पूर्ण करेंगे और अगले 5 वर्षों में प्रत्येक जिले में एक गौवंश विहार स्थापित करेंगे।

- हम प्रदेश में पशु एवं पोल्ट्री चारा निर्माण यूनिट स्थापित करेंगे जिससे किसानों को उचित मूल्य पर चारा मिल सके।
- हम ₹500 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश पोल्ट्री विकास मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत नए अंडा प्रोसेसिंग प्लांट, अंडा कलेक्शन सेंटर्स एवं चिकन प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना करेंगे।

मत्स्य पालन

- हम सभी इच्छुक मछुआरों को 0% ब्याज पर ₹1 लाख तक का सरल ऋण उपलब्ध कराने के लिए मछुआरा क्रेडिट कार्ड प्रदान करना जारी रखेंगे।
- हम भोपाल में एक्वा पार्क का निर्माण समय पर पूरा करेंगे।
- हम बालाघाट, मंडला, शहडोल, छतरपुर एवं इंदौर में मछली बीज हैचरी यूनिट्स की संख्या में वृद्धि करेंगे।

रेशम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन

- हम रेशम समृद्धि योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत, किसानों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए मुफ्त रेशमकीट बीज, सरल ऋण उपलब्ध कराएंगे एवं एक्सपोर्ट बढ़ाने में सहायता भी प्रदान करेंगे।
- हम किसानों को मधुमक्खी पालन एवं शहद बनाने के लिए प्रशिक्षण, निशुल्क मधुमक्खियों के डिब्बे एवं टूलकिट प्रदान करेंगे।
- हम विंध्य हर्बल्स के अंतर्गत मधुमक्खी पालकों को प्रोसेसिंग सुविधाएं, बिक्री सहायता एवं मार्केट लिन्केज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

जैविक खेती को बढ़ावा

- हम जैविक एवं प्राकृतिक खेती क्लस्टर स्थापित करके यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश जैविक खेती में अग्रणी रहे।
- हम गौ-संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनसे गौ मूत्र और गोबर खरीदेंगे एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मीकम्पोस्ट इकाई स्थापित करेंगे, जो उसके लिए राजस्व का स्रोत होगा।





कृषि क्षेत्र के विकास और किसान कल्याण के लिए जो भी पहल जरूरी हैं, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हम इस दिशा में लगातार कदम उठाते आए हैं और आगे भी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे।





जनजातीय कल्याण



जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग पेसा नियमों से लाभान्वित हो रहे हैं

268 ग्राम सभाओं में तेंदूपत्ता संग्रहण, भंडारण एवं मार्केटिंग के कार्य पेसा नियमों के अंतर्गत कराए जा रहे हैं

वनाधिकार कानून के अंतर्गत लगभग 3 लाख पात्र जनजातीय भाई-बहनों को वन अधिकार का पट्टा मिला है

आहार अनुदान योजना के माध्यम से बैगा, सहरिया एवं भारिया बहनों को मासिक ₹1,500 दिए जा रहे हैं, अब तक ₹1,500 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है

प्रदेश के सभी एसटी ब्लॉक में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन शुरू किया गया है

जनजातीय समुदाय के नायकों के सम्मान में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर, पातालपानी स्टेशन का नाम जननायक टंट्या भील के नाम पर, शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान बिरसा मुंडा एवं मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है

सर्वांगीण विकास

- हमने पिछले 3 वर्षों में 1.5 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण में ₹75,000 करोड़ से अधिक का व्यय किया है, और हम अगले 5 वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान करेंगे।
- 2022 में पेसा नियमों के क्रियान्वयन से 1 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभ हुआ है, हम आगे भी इसका लाभ सुनिश्चित करेंगे।
- हम सुनिश्चित करेंगे कि हर जनजातीय परिवार के पास आवास हो एवं हर घर में नल से जल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।
- हम पेसा मोबिलाइजर्स का मासिक मानदेय दोगुना कर ₹8,000 करेंगे।
- हम समयबद्ध तरीके से एसटी प्रमाण पत्रों का वितरण सुनिश्चित करेंगे, इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र के साथ या छात्र के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद एसटी प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के सुलभ क्रियान्वयन के लिए सभी एसटी ब्लॉक एवं जिले में सिंगल विंडो की तर्ज पर जनजातीय समुदाय के लोगों के

लिए समर्पित डेस्क स्थापित करेंगे।

- हम सभी प्रमुख जनजातीय समुदाय के समग्र विकास एवं शिकायतों के समय पर समाधान हेतु बोर्ड स्थापित करेंगे।

आर्थिक सशक्तिकरण

- हम तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति बोरा करेंगे।
- हम सभी एसटी ब्लॉक में पात्र लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों तक का रोजगार प्रदान करेंगे।
- हम रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सभी एसटी ब्लॉक में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करेंगे।
- हम जनजातीय समुदाय के लोगों की आय बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ वन धन विकास केंद्रों एवं वन धन एसएचजी की संख्या दोगुनी करेंगे।
- हम स्थानीय उत्पादों की बिक्री एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, "ट्राइब्स इंडिया आउटलेट" की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में मध्य प्रदेश ट्राइब्स आउटलेट स्थापित करेंगे, इसके अतिरिक्त हम जनजातीय उत्पादों को इ-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करवाएंगे।

समग्र शिक्षा

- मुफ्त स्कूली शिक्षा के साथ साथ हम सभी जनजातीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त उच्च शिक्षा भी प्रदान करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रत्येक एसटी ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की में 3,800 शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे।
- हम जनजातीय छात्रों के लिए सभी एसटी ब्लॉक में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत JEE, NEET, CLAT, UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण उद्यमी योजना के अंतर्गत जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके नौकरी योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

- हम मंडला मेडिकल कॉलेज का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, साथ ही हम खरगोन, धार, बालाघाट एवं सीधी में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी सुनिश्चित करेंगे।
- हम प्रत्येक जनजातीय जिला अस्पताल में निओनेटल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू एवं ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू की स्थापना करेंगे।
- हम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर कवरेज प्रदान के लिए 100 सीएचसी, 500 पीएचसी और 2,300 एसएचसी स्थापित करेंगे।
- हम आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को प्रति माह ₹1,500 प्रदान करते रहेंगे।
- हम मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सा योजना के अंतर्गत चिकित्सकों को ₹75,000 तक का मासिक मानदेय देते रहेंगे, साथ ही इसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- हम 2024 तक सभी एसटी ब्लॉक में मिशन मोड पर सिकल सेल एनीमिया की जांच सुनिश्चित करेंगे एवं आवश्यक उपचार भी प्रदान करेंगे।

सांस्कृतिक संरक्षण

- हम जनजातीय समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए सभी एसटी ब्लॉक में कला भवन स्थापित करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ जनजातीय श्रद्धास्थल संरक्षण मिशन शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत सभी जनजातीय श्रद्धा एवं पूजा स्थलों का नवीनीकरण किया जाएगा।
- हम सभी जनजातीय नायकों की स्मृति में भव्य स्मारकों का निर्माण करेंगे।
- हम चौगान किला, देवगढ़ किला, मंडला किला, चौरागढ़ किला एवं मदन महल का नवीनीकरण करके, उन्हें एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे।
- हम प्रदेश में पारंपरिक एवं जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन करेंगे।
- हम प्रत्येक वर्ष भगोरिया उत्सव का भव्य आयोजन विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे।
- हम टंट्या भील, रानी दुर्गावती, ख्वाजा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे

जनजातीय नायकों की जीवन गाथा, जनजातीय कला एवं संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।



जनजातीय समाज का
कल्याण मेरे लिए व्यक्तिगत
विषय है,
मैंने जनजातीय परंपराओं
को करीब से देखा है,
जिया है, जनजातीय जीवन ने
मुझे देश और उनकी
परंपराओं के बारे में बहुत
कुछ सिखाया है।





उत्तम
शिक्षा एवं
सक्षम युवा

शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

शिक्षा की गुणवत्ता में मध्यप्रदेश 17वें स्थान से 2021 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है

प्रदेश में आईआईटी, AIIMS, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, IIM, IIIT, NIFT, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए गए हैं

बीते साढ़े 3 वर्षों में स्कूली शिक्षकों की लगभग 50 हजार नई भर्तियां की गई हैं

पिछले एक वर्ष में अभियान चलाकर 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की गई है

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक युवाओं का पंजीयन हुआ

पिछले साढ़े 3 वर्षों में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 1.23 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को ₹74,600 करोड़ से अधिक की स्व-रोजगार सहायता दी गई है

युवाओं के समग्र कल्याण एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ युवा नीति-2023 लागू की गई है

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- हमने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम अगले 5 वर्षों में शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर प्रदेश की जीडीपी का 5% तक करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले गरीब परिवार के छात्रों को कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम पीएम पोषण योजना का विस्तार करके कक्षा 8 तक के प्रत्येक छात्र को मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी प्रदान करेंगे।
- हम प्रदेश में शिक्षा संबल योजना शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए ₹1,200 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का पालन करते हुए, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रत्येक छात्र को कक्षा 6 से वोकेशनल शिक्षा मिले।
- हम सीएम राइज स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का पालन करते हुए फ्री मेडिकल जांच प्रदान करेंगे।

- हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान की है और आगे भी विद्यार्थियों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करते रहेंगे।
- हमने मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल प्रदान की है और आगे भी विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल प्रदान करेंगे।
- हमने मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख से अधिक छात्रों को लैपटॉप खरीदने हेतु ₹25,000 की राशि प्रदान की है और आगे भी लैपटॉप खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को स्कूटी खरीदने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता जारी रखेंगे।
- हम सभी मौजूदा 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल शिक्षा केंद्रों में परिवर्तित करके उनका आधुनिकीकरण करेंगे।
- हम प्रत्येक ब्लॉक में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेंगे।

शिक्षा सुविधाओं का विकास

- हम 730 पीएम श्री स्कूल एवं 5,000 सीएम राइज स्कूलों की मिशन मोड में स्थापना करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को स्कूल बस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- हम जबलपुर को प्रदेश के एजुकेशन हब के रूप में विकसित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर 3 नए सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे, जिनके अंतर्गत हम युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- हम अग्निवीर प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर, युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आई.आई.टी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी स्थापित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे।
- हम प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे।

शिक्षकों का सम्मान

- हम प्रदेश में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरेंगे।
- हम प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का समयबद्ध चयन एवं पदोन्नति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना करेंगे।
- हम ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करेंगे।
- हम प्रत्येक जिले में सभी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपग्रेड करेंगे।

रोजगार के अवसर

- हम केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे।
- हम प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर

- नियमित अंतराल में रोजगार मेलों का आयोजन जारी रखेंगे।
- हम स्टार्टअप नीति के अंतर्गत प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या को अगले 5 वर्षों में 10,000 तक करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ सीड फंड स्थापित करके, प्रदेश को स्टार्ट-अप डेवलपमेंट हब के रूप में विकसित करेंगे एवं शैक्षिक संस्थानों में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स की स्थापना को बढ़ावा देंगे।
- हम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में सॉफ्टवेयर युक्त, प्लग-एंड-प्ले मॉडल में को-वर्किंग स्पेस स्थापित करेंगे।

कौशल विकास

- हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं ₹10,000 तक का स्टाइपेंड प्रदान करके नौकरी योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम कौशल विकास एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक संभाग में कोडिंग लैब स्थापित करेंगे।

- हम ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल की तर्ज पर ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करेंगे, ताकि छात्रों को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर मिलें।
- हम प्रदेश में वन ब्लॉक-वन आईटीआई योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में एक सरकारी आईटीआई की स्थापना करेंगे।

स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

- हम प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन करते रहेंगे।
- हम बुनियादी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष हर जिले में मध्य प्रदेश जिला खेल कुंभ का आयोजन करेंगे।
- हम प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने हेतु भोपाल स्थित नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना करेंगे।
- हम ₹500 करोड़ के निवेश के साथ कैप्टन रूप सिंह स्पोर्ट्स मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों एवं

कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल इंप्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे।

- हम वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे।
- हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम एवं खेल मैदान स्थापित करने के कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे एवं मौजूदा स्टेडियम में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करेंगे।
- हम योग उदय योजना शुरू करके स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे एवं योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए योग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे।
- हम सभी सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षित प्रत्येक खिलाड़ी को मुफ्त स्पोर्ट्स किट एवं उपकरण वितरित करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिले।

- हम विशेष अभियान को अंतर्गत प्रदेश के पुरस्कृत खिलाड़ियों के विभिन्न उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित करेंगे।



उड़ान



पूरी दुनिया भारत के
युवाओं की ओर
देख रही है,
क्योंकि आप देश के
ग्रोथ इंजन हैं और
भारत दुनिया का
ग्रोथ इंजन है।





सबका साथ सबका विकास

20 साल विश्वास के विकास के

हर वर्ग के कल्याण में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

पीएम आवास योजना से अब तक लगभग 44 लाख आवास बनाये जा चुके हैं

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से अब तक 4 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है

100 से अधिक दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों में नागरिकों को मात्र ₹5 में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है
वृद्धों, निराश्रितों, दिव्यांगों आदि को वार्षिक ₹3,600 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है

संबल योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 5.25 लाख श्रमिकों को ₹4,917 करोड़ से अधिक के लाभ दिए गए हैं

पीएम स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से अब तक लगभग 13 लाख लघु व्यापारियों को ₹1,366 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा चुका है

देश की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को ₹1 करोड़ की सम्मान निधि, सरकारी नौकरी एवं आवासीय भूखंड दिया जा रहा है

सबका कल्याण

- हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 100 से अधिक रसोई घरों के माध्यम से ₹5 में पौष्टिक भोजन प्रदान किया है, हम रसोई घरों की संख्या में वृद्धि करेंगे, ताकि हर जरूरतमंद को पौष्टिक भोजन मिल सके।
- हम मध्य प्रदेश में अगले 5 वर्षों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वन को जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन प्रदान करेंगे।
- इसके साथ ही, हम पीडीएस लाभार्थियों को रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी भी उपलब्ध कराएंगे।
- हमारा संकल्प है कि मध्यप्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी शुरू करेंगे।

अनुसूचित जाति कल्याण

- हम प्रदेश में सभी अनुसूचित जाति के समुदायों के रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरेंगे।

- हम समयबद्ध तरीके से एससी प्रमाण पत्रों का वितरण सुनिश्चित करेंगे, इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र के साथ या छात्र के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद एससी प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम ₹75 करोड़ के निवेश के साथ अंबेडकर छात्रावास विकास योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मौजूदा छात्रावासों की मरम्मत एवं नवीनीकरण करेंगे।
- हम अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए हर प्रमुख जिले में संत रविदास भवन की स्थापना करेंगे।
- हम सभी प्रमुख अनुसूचित जाति समुदायों के समग्र विकास एवं शिकायतों का समय पर समाधान करने हेतु कल्याण बोर्ड का गठन सुनिश्चित करेंगे, जिसके अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।

सशक्त बनेंगे कारीगर एवं शिल्पकार



भारत की नींव रखने वाले अनगिनत विश्वकर्माओं के अटूट समर्पण को सम्मानित करने हेतु हम पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे और 18 पारंपरिक कारीगर समूहों को लाभ प्रदान करेंगे



प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों
और शिल्पकारों की पहचान

कौशल उन्नयन के अंतर्गत

बुनियादी कौशल
प्रशिक्षण

अग्रिम कौशल
प्रशिक्षण

₹500 का दैनिक
प्रोत्साहन समर्थन



₹15,000 का उपकरण
प्रोत्साहन समर्थन



₹2 लाख तक का
कोलैटरल फ्री ऋण



गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य
गतिविधियों के रूप में मार्केट सपोर्ट

ओबीसी कल्याण

- हम समयबद्ध तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्रों का वितरण सुनिश्चित करेंगे, इसके अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र के साथ या छात्र के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।
- हम ओबीसी युवा प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना करेंगे जिसके अंतर्गत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी।
- हम ग्वालियर में कुशवाहा समाज की आस्था का सम्मान करते हुए एक भव्य लव-कुश मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करेंगे।

विमुक्त जनजाति कल्याण

- हम घुमंतू समुदायों के आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए एक विशेष शिविर लगाएंगे।
- हम घुमंतू समुदाय के परिवारों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे।

- हम विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ₹1 लाख तक का ऋण प्रदान करना जारी रखेंगे।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण

- हम वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह करेंगे।
- हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष में दो बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करेंगे।
- हम वरिष्ठ नागरिकों के राशन की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, अन्न सहायता योजना शुरू करेंगे।

दिव्यांग कल्याण

- हम दिव्यांगों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरेंगे।
- हम दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे।
- हम दिव्यांगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ₹25 लाख तक के कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान करेंगे।

- हम ₹170 करोड़ के निवेश के साथ ग्वालियर में पैरा-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का समय पर निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण

- हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे एवं जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि आवंटित करेंगे।
- हम प्रदेश के ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास करेंगे।
- हम मदरसों में गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में लाएंगे।

व्यापारी कल्याण

- हम व्यापारियों के लिए लंबित जीएसटी मामलों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना करेंगे।
- हम सभी व्यापारियों को जिनकी वार्षिक आय ₹20 लाख से कम है, जीएसटी फाइलिंग के लिए मुफ्त CA सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री माइक्रो ट्रेडर्स दुर्घटना बीमा योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत दुर्घटना के कारण लघु व्यापारियों की मृत्यु या विकलांगता के

मामले में ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

- हम राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लघु व्यापारियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन की व्यवस्था करेंगे।

असंगठित श्रमिक एवं निर्माण श्रमिक कल्याण

- हम श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी असंगठित श्रमिकों का आयुष्मान भारत पीएम-श्रम योगी मानधन योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।
- हम शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निर्माण श्रमिक उन्नयन योजना शुरू करेंगे।
- हम सभी प्रमुख जिलों में विश्राम शाला का निर्माण करेंगे, जिसमें भोजन एवं स्वच्छ पानी जैसी सुविधाएं होंगी।
- हम संबल योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान ₹4,000 और प्रसूति के बाद ₹12,000 प्रदान करते रहेंगे।

- हम रजक समुदाय को उनके पुश्तैनी काम करने के लिए घरेलू दरों पर बिजली प्रदान करेंगे।
- हम सभी शहरी क्षेत्रों में रजक समुदायों के लिए समर्पित लॉन्ड्री क्षेत्र आवंटित करेंगे।

बुनकर एवं कारीगर कल्याण

- हम प्रदेश की स्थानीय कलाकृतियों, हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर के सभी प्रमुख शहरों में मृगनयनी एम्पोरियम की शाखाएं स्थापित करेंगे।
- हम उज्जैन में वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार एवं बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित करेंगे।
- हम देवी अहिल्या बुनकर मेले का आयोजन करेंगे, जिसके अंतर्गत बुनकरों को अपना काम प्रदर्शित करने और वैश्विक बाजार में संपर्क बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- हम बुनकरों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा

योजना और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत जीवन, दुर्घटना और विकलांगता बीमा कवर प्रदान करेंगे।

- हम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले हथकरघा बुनकरों एवं श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

गिग वर्कर कल्याण

- हम गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे, जो उनके कल्याण एवं अधिकारों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा।
- हम सभी गिग वर्कर्स का आयुष्मान भारत, पीएम-जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम-सुरक्षा बीमा योजना आदि के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

ऑटो एवं टैक्सी चालक कल्याण

- हम उन ऑटो-रिक्शा चालकों को कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान करेंगे जो ई-रिक्शा पर स्विच करना चाहते हैं।
- हम सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों का आयुष्मान भारत, पीएम-जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम-सुरक्षा बीमा

योजना आदि के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

- हम पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% तक के आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।

पत्रकार कल्याण

- हम 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को दी जानेवाली श्रद्धा निधि (पेंशन) को बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह करेंगे।
- हम पत्रकारों को सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹40,000 एवं गंभीर बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹1 लाख करेंगे।
- हम पत्रकार की असामयिक मृत्यु की स्थिति में ₹8 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम पत्रकारों के लिए आवास ऋण की सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख करेंगे।

सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण

- हम सभी शहीदों एवं सेना और अर्धसैनिक बल में कार्यरत जवानों के बच्चों को मुफ्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करेंगे।







हमने सबका साथ,
सबका विकास,
सबका विश्वास और
सबका प्रयास के मंत्र
के साथ देश की सेवा
की है।





सुदृढ आधारभूत संरचना



20 साल विश्वास के विकास के

आधारभूत संरचना की नींव रखने में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

2002-03 में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट ₹2,935 करोड़ था, जो इस वर्ष बढ़कर ₹56,000 करोड़ से भी अधिक है

अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत अब तक 5,000 से अधिक सरोवर विकसित किए हैं

ऊर्जा उत्पादन 2003 में 5,173 मेगावाट था, जो अब लगभग 5 गुना बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गया है

वर्ष 2001-02 में सड़कों की लंबाई मात्र 60 हजार किमी थी, जो आज बढ़कर 5 लाख किमी से अधिक हो गई है

प्रदेश में ₹77,000 करोड़ से अधिक की लागत की रेल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है

क्षेत्रीय विकास

- हम बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए हम ₹5,000 करोड़ के निवेश के साथ बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे।
- हम विंध्य विकास बोर्ड एवं महाकौशल विकास बोर्ड की स्थापना करके, इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी चंदेली एवं बुंदेली तालाबों को पुनर्जीवित करने एवं इन्हें अमृत सरोवरों के रूप में विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे।

शहरी विकास

- हम ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना एवं उज्जैन में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- हम सीएम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत मिशन मोड पर सभी नगरों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, यातायात सुधार, सुंदरीकरण, उद्यान विकास से संबंधित कार्य करेंगे।

- हम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के निकटवर्ती जिलों में उपनगरीय क्षेत्रों का विकास कर महानगरीय सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे।
- हम AMRUT 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30 से अधिक शहरों में जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- हम सभी मुख्य शहरों में पीएनजी पाइपलाइन से गैस कनेक्शन की व्यवस्था करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के सहयोग से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पक्के मकान एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- हम प्रदेश में सस्टेनेबल सिटीज़ विकसित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों पर 1,000 शहरी योजनाकारों को नियुक्त करेंगे।





सनी कमलापति
रेलवे स्टेशन

RAHI KAMLA P
RAILWAY STATION

ऊर्जा संसाधन

- हम अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत हर घर को ₹100 में 100 यूनिट बिजली देते रहेंगे।
- हम प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग के मामले में शीर्ष 3 प्रदेशों में शामिल करेंगे।
- हम 2030 तक चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करके, 20,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करेंगे।
- हम खंडवा में दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावाट के ओकरेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण समय से पूरा करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी खराब ट्रांसफार्मरों को मार्च 2024 तक मिशन मोड में बदलेंगे एवं नागरिकों के लिए ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करेंगे।

सड़क विकास

- हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार करेंगे:
 - ◆ 867 किमी लम्बा नर्मदा प्रगति पथ, जो अमरकंटक, डिंडौरी,

शाहपुरा, जबलपुर, नर्मदापुरम, बड़वाह, और अलीराजपुर को जोड़ेगा

- ◆ 676 किमी लम्बा विंध्य एक्सप्रेसवे जो भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली को जोड़ेगा
- ◆ 450 किमी लम्बा मालवा निमाड़ विकास पथ जो मंदसौर, उज्जैन, इंदौर एवं बुरहानपुर को जोड़ेगा
- ◆ 299 किमी लम्बा अटल प्रगति पथ, जो मुरैना, श्योपुर एवं भिंड को जोड़ेगा
- ◆ 330 किमी लम्बा बुंदेलखंड विकास पथ जो भोपाल को छतरपुर से जोड़ेगा
- ◆ 746 किमी लम्बा मध्य भारत विकास पथ जो बैतूल को मुरैना से जोड़ेगा
- हमने प्रदेश में सड़कों की लंबाई 60,000 किमी से बढ़ाकर 5 लाख किमी की है, हम राज्यव्यापी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए और 1 लाख किमी सड़कें बनाएंगे।
- हम प्रदेश में 500 फ्लाइओवर, आरयूबी (RUB) एवं आरओबी (ROB) का एक बड़ा नेटवर्क विकसित करेंगे।
- हम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, एवं उज्जैन में रिंग रोड का निर्माण करेंगे।

- हम प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख प्रदेश राजमार्गों को चार लेन में अपग्रेड करेंगे।
- हम अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश रोड मेटेनेंस एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव किया जाएगा।
- हम ₹3,000 करोड़ के निवेश के साथ भोपाल में 8-लेन एलिवेटेड लेक कॉरिडोर एवं पश्चिम भोपाल बायपास का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

रेल विकास

- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 80 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर ट्रेन शुरू करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे।

सुगम हवाई सेवा

- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर रीवा, सिंगरौली एवं शहडोल हवाई अड्डों का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूर्ण करेंगे।

- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर इंदौर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का समयबद्ध निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित करेंगे।
- हम ग्वालियर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर उज्जैन एयरस्ट्रिप का विस्तार सुनिश्चित करेंगे एवं प्रदेश में अन्य एयरस्ट्रिप का आवश्यकता अनुसार विस्तार करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर एविएशन उद्योग में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजा भोज हवाई अड्डे में मेटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहाल (एमआरओ) हब विकसित करेंगे।

सरल सार्वजनिक परिवहन

- हम 2027 तक भोपाल और इंदौर मेट्रो लाइनों का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करेंगे और जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में मेट्रो लाइनों के विकास और विस्तार के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे।
- हम 3,000 नई इलेक्ट्रिक बस शुरू करेंगे एवं चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था करेंगे।

- हम वन डिस्ट्रिक्ट-वन बस पोर्ट योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बस पोर्ट का आधुनिकीकरण करेंगे।



हम बुनियादी ढांचे का
निर्माण करके सबसे
गरीब और सबसे कमजोर
लोगों की जरूरतों को
पूरा करने के लिए
प्रतिबद्ध हैं।





स्वस्था प्रदेश



20 साल विश्वास के विकास के

प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रखने में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

132 प्रकार की जांच निशुल्क उपलब्ध हैं, जिसका प्रति दिन लगभग 10,000 मरीज लाभ उठा रहे हैं

2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे जो आज बढ़कर 24 हो गए हैं, वहीं MBBS सीटें बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई हैं

साढ़े 3 वर्षों में 800 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और विकास किया गया है

अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 21,000 से 42,000 की गई एवं आईसीयू में बिस्तरों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 2,085 की गई है

स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 11,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए हैं

प्रदेश में 2,000 से अधिक एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा है

प्रदेश में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 7 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 51,000 से अधिक की गई है

सुलभ स्वास्थ्य सेवा

- हम आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए ₹5 लाख से अधिक का व्यय भी सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत उठाएंगे।
- हम नए 500 जन औषधि केंद्र शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिल सकें।
- हम 132 प्रकार की जाँच निशुल्क उपलब्ध कर रहे हैं, साथ ही हम इस व्यवस्था के अंतर्गत जाँच की संख्या में वृद्धि कर मुफ्त डायग्नोसिस की सुविधा प्रदान करते रहेंगे।
- हम प्रदेश के रेयर डिजीज के रोगियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ₹20 लाख की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम 2025 तक मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएंगे एवं टीबी रोगियों की मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹1,000 करेंगे।
- हम वन ब्लॉक-वन डायलिसिस यूनिट योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हर ब्लॉक में डायलिसिस यूनिट स्थापित करके मरीजों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराएंगे।

- हम निजी अस्पतालों में मरीजों के चिकित्सा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे एवं अत्यधिक फीस को रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करेंगे।

कुशल मानव संसाधन

- हमने मेडिकल सीटों में 4,000 से अधिक की वृद्धि की है, हम अगले 5 वर्षों में 2,000 और मेडिकल सीटें जोड़ेंगे।
- हम मिशन मोड पर डॉक्टर, नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियों को भरते रहेंगे।



मजबूत स्वास्थ्य संरचना



₹20,000 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश निरामय इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हर स्तर पर सुचारु स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे



अटल मेडिसिटी स्थापित करेंगे



प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस स्थापित करेंगे



प्रमुख शहरों में कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेंटर स्थापित करेंगे



वन लोकसभा-वन मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत हर लोक सभा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे



वन डिस्ट्रिक्ट-वन नर्सिंग कॉलेज योजना के अंतर्गत हर जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे



वन ब्लॉक-वन ब्लड बैंक योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में ब्लड बैंक स्थापित करेंगे



एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे



अस्पताल एवं आईसीयू में बिस्तरों की संख्या को दोगुना करेंगे

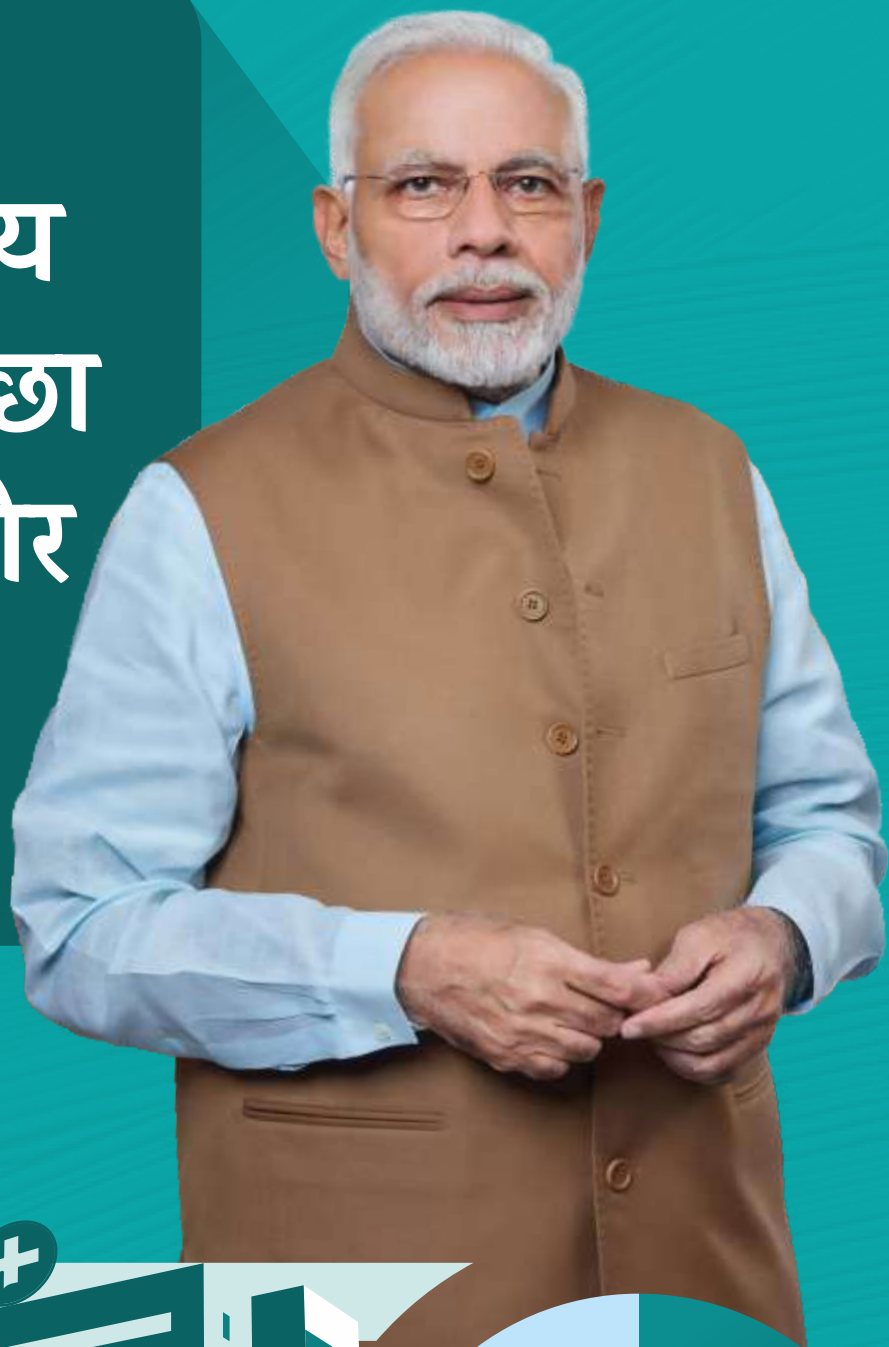


मध्य प्रदेश
आरोग्यम्
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वीरपुर डेम सीहोर
वि. वि. इलाहा निला गीहोरा

एन.सी.डी. लॉजिस्टिक्स
एन.सी.डी. लॉजिस्टिक्स
एन.सी.डी. लॉजिस्टिक्स
एन.सी.डी. लॉजिस्टिक्स

AMBULANCE
PATIENT TRANSPORT
MH 39AD5340

हमारा लक्ष्य
सबका अच्छा
स्वास्थ्य और
कल्याण।





प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास

20^{साल} विश्वास के विकास के

औद्योगिक विकास के लिए हमारी प्रमुख उपलब्धियां

प्रदेश का औद्योगिक विकास दर 2003 में -0.61% थी, जो
2023 में बढ़कर 24% हो गई है

प्रदेश का निर्यात 2022-23 में बढ़कर लगभग ₹66,000
करोड़ से अधिक हो गया है

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में ₹15 लाख करोड़ के
निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 29 लाख से अधिक रोजगार
के अवसर पैदा होंगे

निवेश को बढ़ावा देने के लिए 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर:
भोपाल-इंदौर, भोपाल-बीना, जबलपुर-कटनी -सतना-
सिंगरौली एवं मुरैना-ग्वालियर-शिवपुरी-गुना का निर्माण
शुरू किया गया है

प्रदेश में 263 औद्योगिक क्षेत्र एवं 59 एमएसएमई क्लस्टर
स्वीकृत हुए, साथ ही प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को
₹2,500 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया है

आर्थिक विकास

- हम 2030 तक जीएसडीपी को ₹45 लाख करोड़ तक बढ़ाने और मध्य प्रदेश को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हमने प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2001 में ₹11,000 से बढ़ाकर 2023 में ₹1.4 लाख की है, हम अगले 7 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम प्रदेश के निर्यात को ₹2 लाख करोड़ तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम प्रदेश में लगभग ₹20 लाख करोड़ के निवेश (FDI) को आकर्षित करेंगे।

मजबूत इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर

- हम 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, वाराणसी-मुंबई एक्सप्रेसवे एवं चम्बल एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करेंगे।
- हम प्रदेश में प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए महाकौशल एवं मालवा-निमाड़ क्षेत्रों में टिम्बर (लकड़ी) एवं बैम्बू (बांस)

के लिए दो नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) स्थापित करेंगे।

- हम प्रगति उद्योग मिशन शुरू करके सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण करेंगे।
- हम पूर्वी मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कटनी-जबलपुर एवं रीवा-सतना के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे।
- हम 22 इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना समय से पूर्ण करेंगे एवं कपड़ा, फ़ूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग, आईटी, पर्यटन, एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 78 और इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित करेंगे।
- हम प्रदेश को कपड़ा, ऑटोमोबाइल एवं फार्मास्यूटिकल उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- हम भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रतलाम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर मिशन मोड पर मध्य प्रदेश में 20 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास करेंगे।

पीएम मोदी जी का संकल्प



मध्य प्रदेश अगले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा

प्रमुख प्रोजेक्ट
जिसे हम समय से
पूरा करने के लिए
प्रतिबद्ध हैं



₹49,000 करोड़ के निवेश से बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से 1 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर



इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क



शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगर मालवा, नर्मदापुरम एवं मक्सी में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र



धार में 'पीएम मित्र' मेगा टेक्सटाइल पार्क



पूर्वी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी-मुंबई आद्योगिक कॉरिडोर



भोपाल में रेयर अर्थ मेटल्स एवं टाइटेनियम थीम पार्क

विशिष्ट उद्योग

- हम ₹14,000 करोड़ के निवेश से पन्ना में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क को समय से पूरा करेंगे जिससे 1 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर, चंबल क्षेत्र में एयरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण निर्माण पार्क स्थापित करेंगे।
- हम नर्मदापुरम में विद्युत एवं रिन्यूएबल एनर्जी मैनुफैक्चरिंग जोन स्थापित करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
- हम हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आएंगे।
- हम प्रदेश में EV मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए EV प्रमोशन पॉलिसी लेकर आएंगे।
- हम प्रदेश में EV मैनुफैक्चरिंग पार्क का निर्माण करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर, बिलौआ, ग्वालियर में बनने वाले प्लास्टिक पार्क को समय से पूरा करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
- हम भोपाल में फैब्रिक और गारमेंट यूनिट एवं इंदौर के पास रेडीमेड गारमेंट यूनिट का

काम समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

- हम ₹50 करोड़ के निवेश के साथ नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

फार्मा उद्योग

- हम उज्जैन में प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेंगे।
- हम ₹5,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ मोहसा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में मेगा फार्मा पार्क स्थापित करेंगे।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों)

- हम रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 10 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करेंगे।
- हम एमएसएमई को ऋण, बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास एवं एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करने के लिए समर्थन पोर्टल (सिंगल विंडो मैकेनिज्म) स्थापित करेंगे।
- हम ₹5,000 करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश में कार्यरत एमएसएमई को न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करेंगे।

- हम सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का आर्थिक आपदाओं के समय संरक्षण करने हेतु ₹500 करोड़ के निवेश के साथ डिस्ट्रिब्यूटेड एसेट फण्ड स्थापित करेंगे।
- हम उत्पादन क्षमता को मजबूती देने के लिए हर जिले में मार्केटिंग एवं एक्सपोर्ट असिस्टेंस सेंटर्स की स्थापना करेंगे।
- हम अगरबत्ती निर्माताओं को ऋण, सब्सिडी अन्य तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- हम पारंपरिक खिलौनों के मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 टॉय मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करेंगे।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग

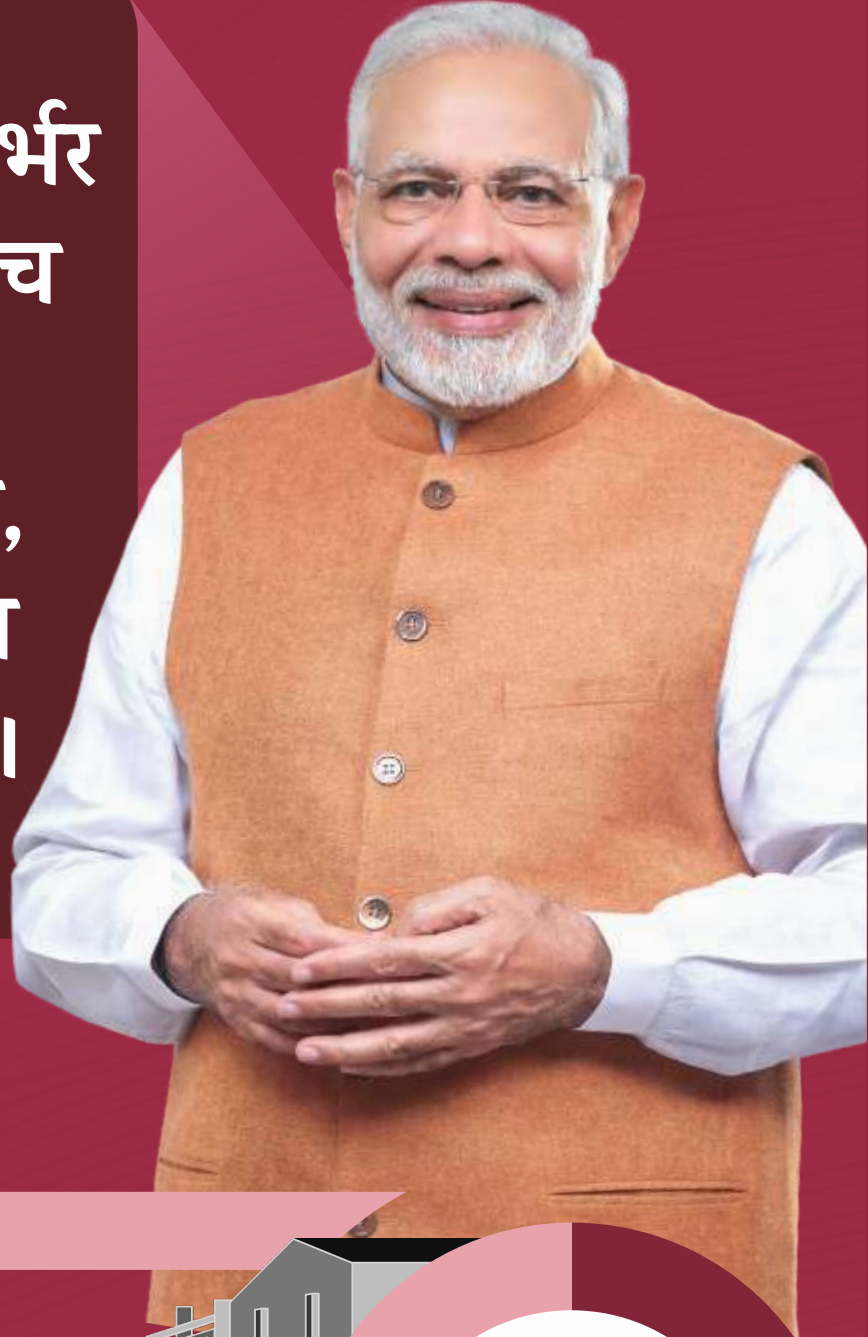
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रत्येक संभाग में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम इंदौर के क्रिस्टल आईटी पार्क की तर्ज पर भोपाल के पास साइबर सिटी की स्थापना करेंगे।

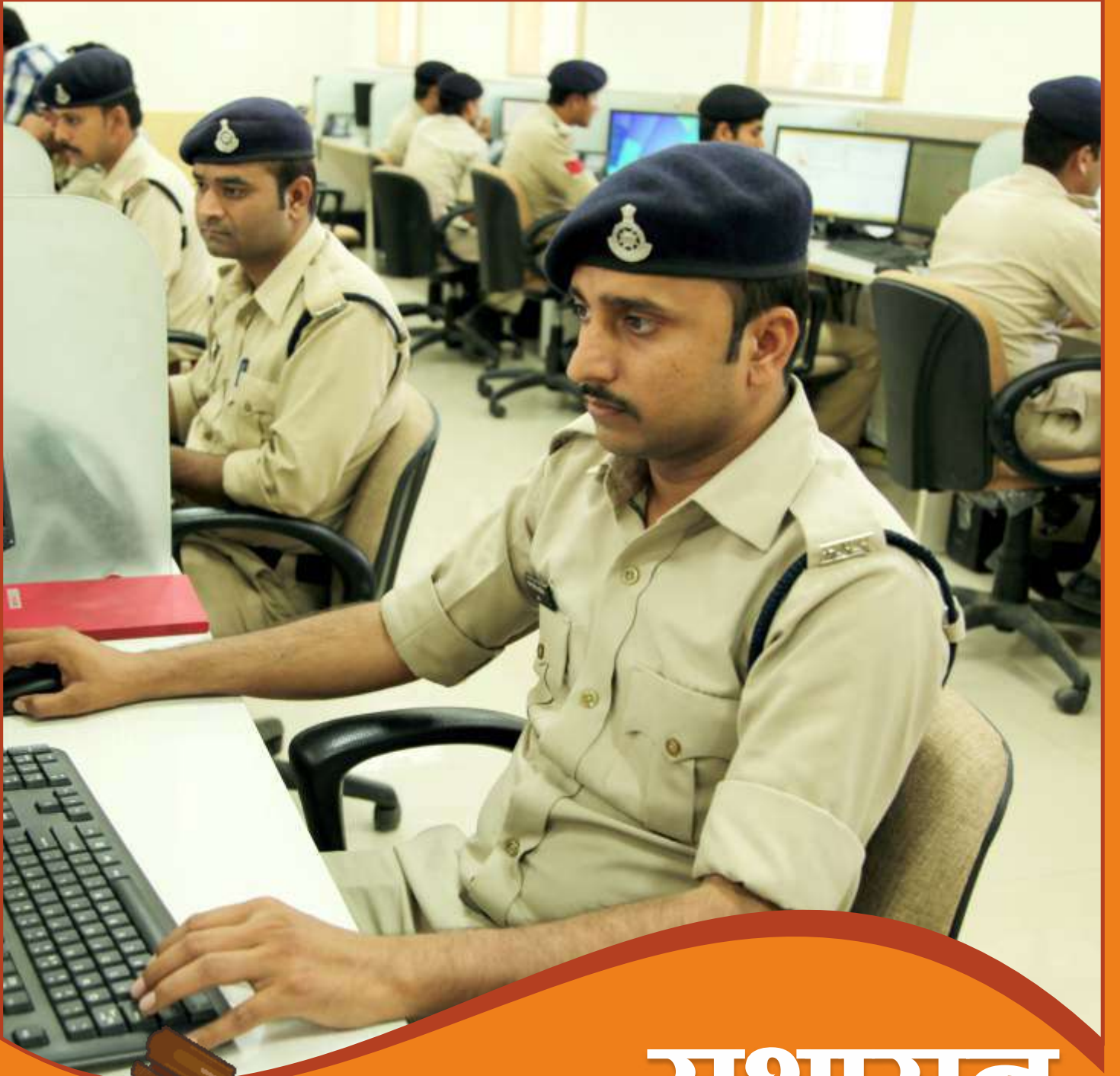
- हम इंदौर में डेटा सेंटर पार्क एवं स्टार्टअप पार्क का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- हम भोपाल एवं जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग पार्क को समयबद्ध तरीके से पूरा करके, लाखों युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम प्रदेश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन (फैब) की सुविधा स्थापित करेंगे, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में मध्य प्रदेश की स्थिति को मजबूत करेगी।





भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच चीजें जरूरी हैं-
इरादा, इनोवेशन,
निवेश, समावेश
और इंफ्रास्ट्रक्चर।





सुशासन एवं कानून व्यवस्था

20 साल विश्वास के विकास के

सुशासन के क्षेत्र में हमारी प्रमुख उपलब्धियां

लोक सेवा गारंटी कानून लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश मध्य प्रदेश है जिसके अंतर्गत अब तक 600 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही है

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज 2.35 करोड़ से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया गया है

सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष की सेवा के उपरांत चतुर्थ समयमान-वेतनमान दिया गया है

संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान लाभ दिए गए हैं

भू-माफिया, चिटफंड माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, राशन माफिया आदि के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की गयी है

धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है

सुशासन

- हम प्रदेश की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए जिले, उपखंड एवं तहसील बनाने की प्रक्रिया जारी रखेंगे।
- हम एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के अंतर्गत चयनित 42 ब्लॉक के काम को समय से पूरा करेंगे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी नागरिक सम्बन्धी सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

सरकारी कर्मचारी केंद्रित नीति

- हम प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सभी रिक्त स्वीकृत पदों को समयबद्ध तरीके से भरते रहेंगे।
- हम सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को समय समय पर संशोधित करते रहेंगे।
- हम सरकारी कर्मचारियों के सभी विभागों में सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाएंगे।
- हम नियमित कर्मचारियों के समान कार्यभारित (वर्क चार्ज) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त 300 दिवस के अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान करेंगे।

- हम ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केन्द्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधा प्रदान करेंगे।
- हम कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में सरलीकरण करेंगे।

ग्रामीण विकास अधिकारी केंद्रित नीति

- हम पटेलों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी नियुक्त समयबद्ध क्रम में सुनिश्चित करेंगे एवं राजस्व प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जैसे विषयों में पटेलों का भरपूर सहयोग लिया जाएगा।
- हम ग्राम पंचायतों के कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए कोटवारों को नियुक्त समयबद्ध क्रम में सुनिश्चित करेंगे।
- हम बिना सेवा भूमि वाले कोटवारों का मानदेय ₹8,000 और सेवा भूमि वाले कोटवारों का ₹2,000 तक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम कोटवारों को सेवानिवृत्ति के बाद ₹1 लाख की राशि देना जारी रखेंगे।

- हम सभी कोटवारों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे।
- हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को ₹4,250 प्रति माह सम्मान राशि प्रदान करना जारी रखेंगे।

पुलिस कर्मचारी केंद्रित नीति

- हम सभी पुलिस कर्मियों को पांचवा वेतनमान अगले 6 महीने में प्रदान करेंगे।
- हम सभी पुलिस कर्मियों को निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करेंगे।
- हम मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा कैशलेस योजना का विस्तार करके, सभी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं उनके परिवारों को भी जोड़ेंगे।

नागरिकों की सुरक्षा

- हमने भोपाल एवं इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू की है, हम अगले 2 वर्षों में इसका विस्तार जबलपुर एवं ग्वालियर में करेंगे।
- हम प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क एवं इमरजेंसी

ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेंगे।

- हम प्रदेश भर में आवश्यकता अनुसार नए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करेंगे।
- हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करेंगे।
- हम फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान संख्या 4 से बढ़ाकर 10 करेंगे।
- हम पुलिस मॉर्डनाइजेशन फंड के अंतर्गत पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार प्रदान करेंगे, साथ ही सभी मौजूदा पुलिस स्टेशनों की मरम्मत एवं आवश्यकता के अनुसार नए स्टेशनों का निर्माण करेंगे।





सुशासन ही
राष्ट्र की
प्रगति की
कुंजी है।





सांस्कृतिक धारोहर एव विकसित पर्यटन



20^{साल} विश्वास के विकास के

सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए हमारी प्रमुख उपलब्धियां

ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची
प्रतिमा स्थापित की गई है

एकात्म धाम के साथ यहां अद्वैत वेदांत संस्थान एवं अद्वैत
वन विकसित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में लगभग 8 लाख वृद्धजनों
के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की गई है एवं हवाई जहाज
से भी तीर्थ यात्रा प्रारम्भ की गई है

प्रदेश के 18 शहरों को पवित्र नगरों का दर्जा दिया गया है

सांस्कृतिक नायकों का सम्मान

- हम ₹100 करोड़ के व्यय के साथ सागर में शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक का निर्माण कार्य पूरा करेंगे।
- हम ₹150 करोड़ के व्यय के साथ धरोहर संरक्षण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण करेंगे एवं वहां विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के व्यय के साथ जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण कार्य पूरा करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के व्यय के साथ छतरपुर में महाराज छत्रसाल का भव्य स्मारक बनाएंगे।
- हम ग्वालियर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भव्य स्मारक एवं रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य पूरा करेंगे।
- हम ग्वालियर में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य पूरा करेंगे।
- हम भोपाल में वीर भारत स्मारक विकसित करेंगे, जिसमें क्रांतिकारियों एवं आजादी के नायकों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा।

- हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सीहोर में शहीद हुए 356 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भव्य स्मारक का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- हम भोपाल में महाराणा प्रताप लोक के निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।

आस्था एवं संस्कृति का संरक्षण

- हम ₹500 करोड़ के निवेश के साथ सुरम्य ग्रामीण मंदिर मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मंदिरों के बुनियादी ढांचे का विकास, सौंदर्यीकरण एवं रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी पुरोहितों को ₹5,000 का मासिक मानदेय प्रदान करेंगे।
- हम बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक विशेष बोर्ड बनाएंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मंदिर की जमीन राज्य सरकार नीलाम न कर सके एवं मंदिरों के पुजारी एक साल के लिए जमीन लीज पर दे सकें।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं संरक्षण के पथ पर अग्रणी भूमिका निभाएगा मध्य प्रदेश



हम प्रदेश में 13 सांस्कृतिक एवं धार्मिक लोक
के निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे



ओरछा में राम राजा लोक



चित्रकूट में वनवासी राम लोक



सलकनपुर में देवी लोक



महेश्वर में देवी अहिल्या लोक



जानापाव में भगवान परशुराम लोक



दतिया में पीतांबरा माई महल लोक



जामसांवली में हनुमान लोक



मैहर में माँ शारदा लोक



पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक



अमरकंटक में मां नर्मदा का महालोक



सतना में वैकटेश लोक



चंदेरी में जागेश्वरी माता मंदिर लोक



आगर-मालवा में बाबा बैजनाथ का लोक

हम खरगोन में ओंकारेश्वर मंदिर, मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर, भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर और पचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव मंदिर जैसे प्रमुख शिव मंदिरों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।

हम मैहर में शारदा माता मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा देवी शोणदेश शक्ति पीठ, उज्जैन में हरसिद्धि माता शक्तिपीठ जैसे प्रमुख शक्तिपीठों का नवीनीकरण और रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।

भाषाई संस्कृति एवं कला का संरक्षण

- हम प्रदेश की भाषाई संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न साहित्य अकादमियों की स्थापना करेंगे:
 - ◆ बघेली साहित्य को समर्पित महाराजा मार्तण्ड सिंह बघेली अकादमी
 - ◆ बुंदेली साहित्य को समर्पित महाराजा छत्रसाल बुंदेली अकादमी
 - ◆ गोंडी साहित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए राजा शंकर शाह गोंडी अकादमी
 - ◆ भीली साहित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए टंड्या भील अकादमी
- हम ग्वालियर, मालवा, मैहर एवं खजुराहो के शास्त्रीय संगीत विरासत के संरक्षण के लिए मौजूदा संगीत एवं कला केंद्रों का नवीनीकरण करेंगे।
- हम भारत भवन का कायाकल्प कर उसे देश के सांस्कृतिक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करेंगे।

कलाकार कल्याण

- हम जनजातीय और लोक कलाकारों के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन दर बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिदिन और दैनिक भत्ता बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन करेंगे।
- हम गंभीर बीमारियों से पीड़ित या पूर्ण रूप से विकलांग कलाकारों और लेखकों को ₹1 लाख तक की सहायता प्रदान करेंगे।
- हम कलाकारों की मृत्यु के उपरान्त उनके परिवारों को ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

नर्मदा और अन्य प्रमुख नदियों का संरक्षण

- हम ₹1,042 करोड़ के निवेश के साथ नमामि नर्मदा के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे।
- हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ अमरकंटक में नर्मदा शक्ति धाम कॉरिडोर विकसित करेंगे।
- हम घाट आधुनिकीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत नर्मदा एवं क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों के घाटों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करेंगे।
- हम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा परिक्रमा पथ

विकसित करेंगे एवं नर्मदा परिक्रमा पथ पर आश्रय कक्षों का निर्माण करेंगे।

- हम प्राथमिकता से नर्मदा नदी के किनारे स्थित सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं विकास करेंगे।
- हम उज्जैन में क्षिप्रा महोत्सव एवं जबलपुर में नर्मदा महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करेंगे।
- हम स्थानीय समुदायों को नर्मदा नदी के किनारे होम-स्टे सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- हम निर्मल एवं अविरल क्षिप्रा सुनिश्चित करने के लिए क्षिप्रा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाएंगे।

पर्यटन हब

- हम ₹7,500 करोड़ के व्यय के साथ पर्यटन कौशल मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
- हम ग्वालियर को ग्लोबल क्रिएटिव सिटी और उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित करेंगे।
- हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के दायरे में आने वाले व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- हम गो-लोकल कैम्पेन शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत स्थानीय होम-स्टे, फूड एवं टूरिज्म

स्थलों को बढ़ावा देंगे।

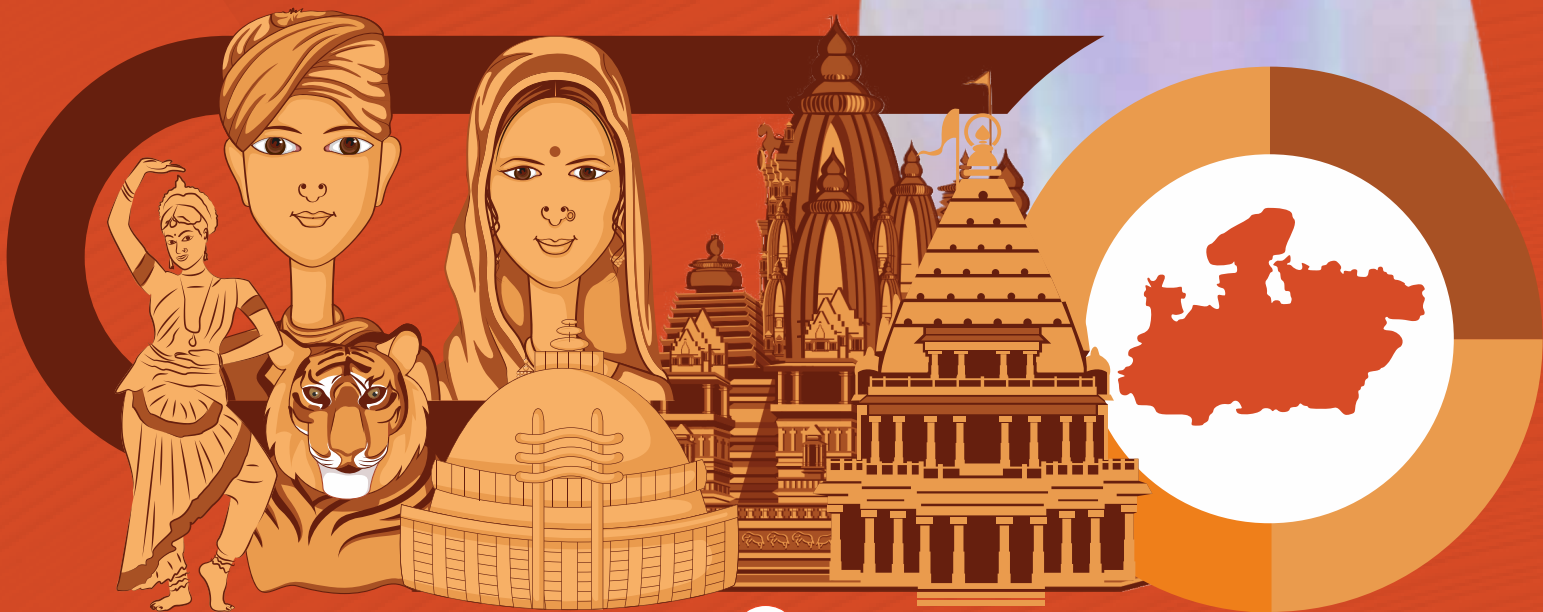
- हम प्रत्येक संभाग में ₹200 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करेंगे।
- हम एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा नदी के किनारे चुनिंदा स्थानों पर कायाकिंग एवं कैनोइंग स्टेशन स्थापित करेंगे।
- हम निमाड़, मालवा एवं चंबल के व्यंजनों की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन करेंगे।
- हम खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करेंगे।

फिल्म टूरिज्म

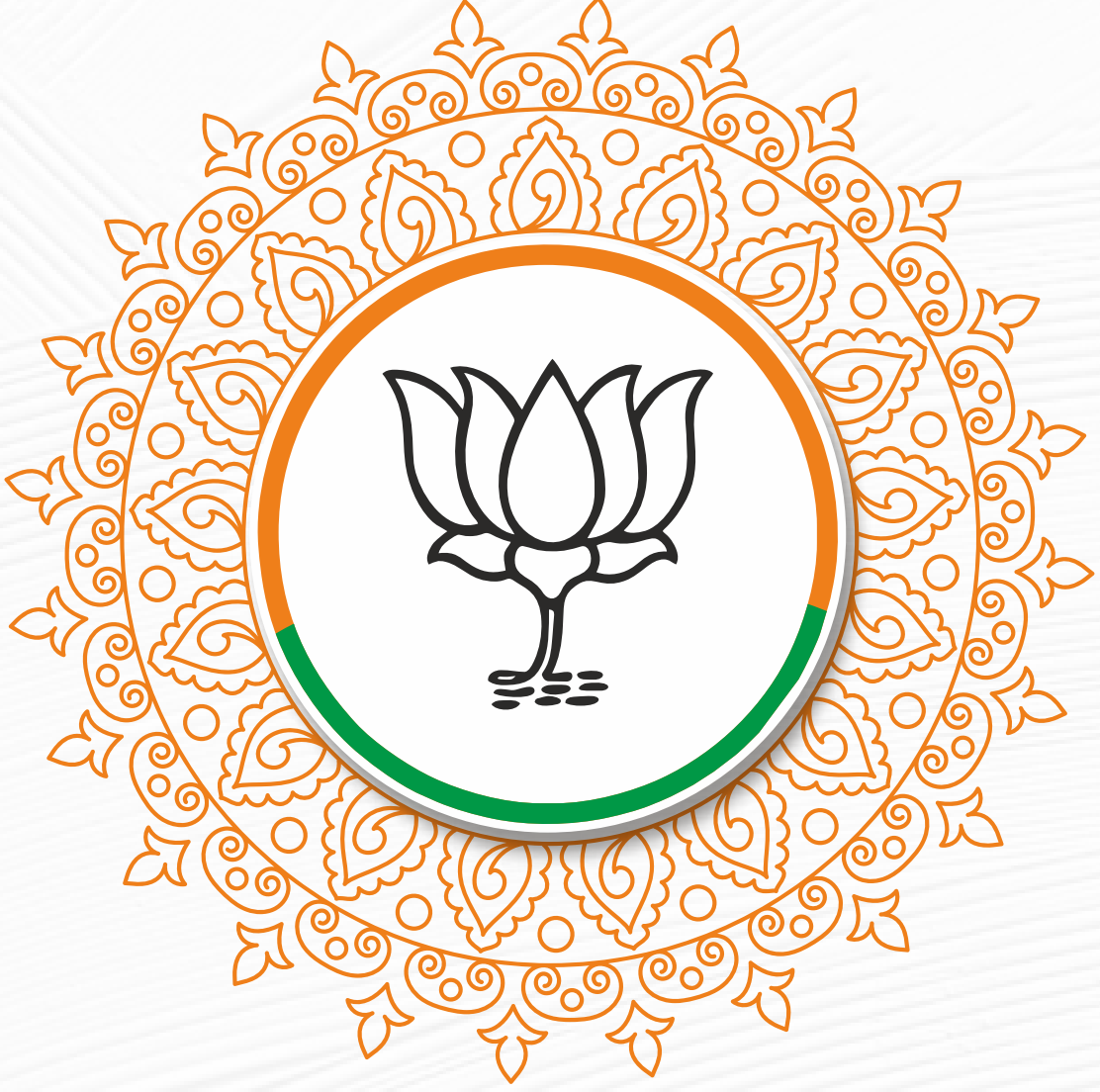
- हम ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश में ग्रैंड फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे, जिसमें फिल्म निर्माण से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- हम तानसेन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थापित करके लोक नृत्य, संगीत एवं रंगमंच से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम स्टेट स्कूल ऑफ़ ड्रामा को नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा की तर्ज़ पर विकसित करेंगे।



आज पर्यटन केंद्रों का
विकास सिर्फ सरकारी
योजनाओं का
हिस्सा नहीं, बल्कि
जनभागीदारी
का अभियान है।

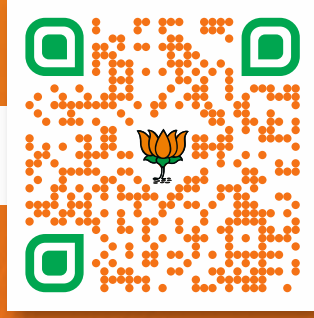






भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश

संकल्प पत्र डाउनलोड करने हेतु



QR Code को स्कैन करें

भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश



कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं